A Daily News Magazine
भोपाल
बुधवार, 17 जून, 2026
भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित
वर्ष 23, अंक 285, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

# रिकॉर्ड के मोर्चे पर कौन भारी, कौन कमजोर ?

**उमेश चतुर्वेदी**

इस बार 11 जून की तारीख भारतीय इतिहास के लिए विशेष बनकर आई। इसी दिन निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा दिन शासन चलाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। इसके पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा 4398 दिन प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के नाम है। मौजूदा दौर विशेषकर विजुअल मीडिया के वर्चस्व का दौर है। विजुअल मीडिया की चूंकि उत्सवधर्मिता केंद्रित है, लिहाजा इस रिकॉर्ड को लेकर सत्ता पक्ष में उत्साह का माहौल होना ही था और ऐसा है भी। लेकिन इसे लेकर आलोचनाओं की बाढ़ भी आ गई है। विशेषकर प्रगतिशील खेमे से मोदी के इस रिकॉर्ड को लेकर तंज में आलोचनाएं की जा रही हैं। इन आलोचनाओं का भाव कुछ वैसे ही है, जैसे कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। आलोचकों की नजर में कहावत के राजा भोज नेहरू हैं और गंगू मोदी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ अरसा पहले संसद को संबोधित करते हुए देश के विकास में अतीत के हर प्रधानमंत्री के योगदान को याद किया था। इतिहास क्रम में हर प्रधानमंत्री ने कुछ न कुछ योगदान दिया ही है। हर प्रधानमंत्री की युगीन आवश्यकताएं और परिस्थितियां अलग रही हैं।

इसलिए अव्वल तो ऐसी तुलनाएं होनी ही नहीं चाहिए थी। क्योंकि नेहरू के युग में भारत की जो स्थिति थी, वह अब नहीं है। इतिहास का कोई खंड कठिन होता है तो कोई आसान। इसलिए इतिहास के काल खंड की बुनियाद पर उस दौर के शासक की परख होनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य का शासक अपनी उपलब्धियों का जश्न नहीं मना सकता।

प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जिस तरह का राजनीतिक माहौल स्थापित हो चुका है, उसमे अगर प्रगतिशील खेमा और कांग्रेस की आलोचना के केंद्र में मोदी ना रहें तो ही हैरत होगी। प्रगतिशील खेमा मोदी को कमतर दिखाने की कोशिश में नेहरू को सबसे ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस आलोक में इतिहास के तथ्यों को जांचना जरूरी है। इसमें दो राय नहीं कि जब 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली, तब पंडित जवाहर लाल नेहरू ने ही देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। लेकिन वह किसी एक दल विशेष यानी कांग्रेस की ही सरकार नहीं थी, बल्कि एक तरह से वह राष्ट्रीय सरकार थी, जिसमें अंबेडकर भी थे और श्यामाप्रसाद मुखर्जी भी।

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी और लॉर्ड एटली प्रधानमंत्री बने। एटली ने चुनावी वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो भारत को स्वाधीनता दी जाएगी। इसी सिलसिले में 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। मिशन के सामने सवाल यह था कि सत्ता का हस्तांतरण किसे किया जाएगा, क्योंकि उन दिनों भारत में दो बड़े और प्रमुख दल थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। लेकिन सत्ता किसे सौंपी जाए, इस सवाल के साथ ही भारत की भावी सरकार और विधान को तैयार करने के लिए संविधान सभा का चुनाव 1946 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलीं। दूसरे दलों और निर्दलीयों को 15 सीटें मिलीं थी। इसके पहले प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस को 923 और मुस्लिम लीग को 425 सीटें मिली थीं। इसके बाद सबसे बड़ा दल होने के नाते कांग्रेस को ही सत्ता हस्तांतरण होना तय हुआ। उन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए अधिकांश प्रांतीय समितियों ने सरदार पटेल का नाम आगे किया था, जबकि कुछ ही प्रांतीय कांग्रेस समितियों ने जवाहर लाल नेहरू का नाम आगे किया। चूंकि गांधी जी पहले ही कह चुके थे कि उनके बाद जवाहर उनकी भाषा बोलेगा यानी सत्ता उन्हें मिलेगी, इसलिए वे ही अध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद सत्ता हस्तांतरण प्रक्रिया के तहत 2 सितंबर 1946 को 'अंतरिम सरकार' का गठन हुआ, जिसमें नेहरू जी को 'वायसराय की कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष' बनाया गया, उस पद का नाम प्रधानमंत्री नहीं था। इसे अंतरिम सरकार कहा गया। भले ही कुछ लोग सुविधा के लिए नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल को उसी दिन से मान लेते हैं। देश को 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947' के तहत देश को आजाद घोषित किया गया। इस कानून के मूल पाठ में कहीं भी 'प्राइम मिनिस्टर' या प्रधानमंत्री शब्द नहीं लिखा हुआ है। हालांकि पंद्रह अगस्त 1947 की आधी रात को नेहरू ने स्वाधीन सरकार के मंत्री के रूप में शपथ ली, भले ही वे उसके मुखिया थे। नेहरू ने अंग्रेजी में शपथ लेते हुए 'ऑफिस ऑफ मिनिस्टर' यानी मंत्री पद की शपथ ली थी, प्रधानमंत्री पद की नहीं। इसके बाद ही उन्होंने 'नियति से साक्षात्कार' वाला प्रसिद्ध भाषण दिया था। मोदी को सबसे लंबे समय तक बतौर निर्वाचित प्रधानंत्री काम करने के रिकॉर्ड को गलत साबित करने वाला प्रगतिशील तबके का तर्क है कि 1946 के चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ा दल बन कर उभरी और उसके निर्वाचित नेता के तौर पर नेहरू ने सरकार चलाई। लेकिन हकीकत यह है कि 1946 का चुनाव वयस्क मतदान के अधिकार और एक व्यक्ति, यह सिर्फ दस प्रतिशत लोगों के मतदान की बुनियाद पर हुआ चुनाव था। स्वाधीन भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 के बीच हुआ। जिसमें कांग्रेस को 364 सीटें मिलीं। इसी नतीजे के आधार पर पंडित नेहरू ने 13 मई 1952 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 27 मई 1964 को मृत्यु पर्यंत अपने पद पर रहे। इसी लिहाज से नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन ही होता। आधुनिक सार्वभौम मतदान के अधिकार और सिद्धांत के लिहाज से देखें तो पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर असल कार्यकाल 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक का ही होता है।

रही बात नेहरू और मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों की, तो इसकी तुलना की जा सकती है। भारत की आजादी के वक्त देश में बीस विश्वविद्यालय थे, जिसे नेहरू ने अपने कार्यकाल में 64 तक पहुंचा दिया था। इस लिहाज से देखें तो मोदी के कार्यकाल में देश में साढ़े पांच सौ से ज्यादा विश्वविद्यालय हो चुके हैं। नेहरू समर्थक कह रहे हैं कि आजादी के वक्त देश में 15 मेडिकल कॉलेज थे, जिनकी संख्या बढ़ाकर नेहरू ने 81 कर दी थी। लेकिन जब मोदी ने कार्यकाल संभाला तो देश में 393 मेडिकल कॉलेज थे, जिसे उन्होंने 818 तक कर दिया है। 431 मेडिकल कॉलेज तो 2014 के बाद ही बने हैं। बेशक नेहरू अपनी विदेश नीति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मोदी ने भारत के स्वत्व बोध को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खूब बढ़ाया है।

**( प्रभासाक्षी डॉट कॉम पर प्रकाशित लेख के संपादित अंश)**

## सुप्रभात

प्रेम पढ़ाई स्वप्न थे, भरा आत्म विश्वास।
अँधियारे का भय नहीं, जेबों भरी उजास।।
दुनिया छोटा शहर थी, कुछ प्यारे- से मित्र।
छोटे सपने पास थे, उजले-धुंधले चित्र।।
संकल्पों से थे भरे, कुछ करने की चाह।
दुनिया के विस्तार में, सच से बेपरवाह।
कूदे जीवन- युद्ध में, किया बहुत संघर्ष।
संघर्षों से ही मिला, जीवन को उत्कर्ष।।
धीरे- धीरे कम हुआ, भौतिकता से मोह।
मोह कहूँ या फिर कहूँ, गहरी अंधी खोह।।
ऊँची- ऊँची सीढ़ियाँ, बढ़ने लगी थकान।
जाने कितनी दूर है, मेरा नया ठिकान।।

**- शशिकांत गीते**

बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाएं और जन-कल्याण के लिए 24 हजार 200 करोड़ रूपये की स्वीकृति

# मेगा स्वास्थ्य सेवा अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति के प्रस्ताव पर उप समिति गठित

- **मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय**

**भोपाल (नप्र)।** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। बैठक में मध्यप्रदेश के बुनियादी ढांचे और जन-कल्याण को बड़ी रफ्तार देते हुए कुल 24,200 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण सहित कुल 19,472 करोड़ 29 लाख रुपये का पुनरीक्षित बजट स्वीकृत किया गया। राज्य में विश्वस्तरीय सुपर-स्पेशियलिटी चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने और परोपकारी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मेगा स्वास्थ्य सेवा अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति 2026 लागू करने के प्रस्ताव पर मंत्रि-परिषद ने 5 सदस्यीय मंत्रि-मण्डल उप समिति का गठन किया है। समिति सभी संबंधित पहलुओं का अध्ययन कर रिपोर्ट देगी। मंत्रि-परिषद ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए रीवा, देवास और गुना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आउटसोर्स मॉडल पर चलाने का पायलट प्रोजेक्ट भी मंजूर किया गया।

वन्य-प्राणी संरक्षण और संवेदनशील क्षेत्रों के 94 गांवों के विस्थापन व मुआवजे के लिए 16वें वित्त आयोग की अवधि 2026-2031 के तहत 2 हजार 381 करोड़ 15 लाख रुपये आवंटित किए हैं। सामाजिक और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देते हुए जनजातीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक व आवासीय सुविधाओं के लिए 687 करोड़ रुपये और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से रेशम उत्पादन की विभिन्न योजनाओं के लिए 639 करोड़ 25 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।

मंत्रि-परिषद द्वारा श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन,औद्योगिक सुरक्षा और श्रमिक कल्याण योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए 531 करोड़ 78 लाख रुपये तथा स्थानीय निकायों के वित्तीय प्रबंधन व ऑडिट व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए स्थानीय निधि संपरीक्षा के संचालन के लिए 492 करोड़ 45 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

- **इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की पुनरीक्षित लागत और अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए 19 हजार 472 करोड़ 29 लाख रूपये की स्वीकृति-** मंत्रि-परिषद ने इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की मूल लागत 7 हजार 500.80 करोड़ रूपये में 5 हजार 388.58 करोड़ रूपये की अतिरिक्त लागत जोड़कर पुनरीक्षित लागत 12 हजार 889.38 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त उद्योग के स्वीकृत मानदंडों के अनुसार परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण पीपीपी घटक एवं आंतरिक ऋण के प्रभाव को सम्मिलित करते हुए 6 हजार 582.91 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस तरह कुल 19 हजार 472 करोड़ 29 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। अतिरिक्त वित्त पोषण में भारत शासन और मध्यप्रदेश शासन द्वारा 1,696 करोड़ 74 लाख रूपये की अतिरिक्त इक्विटी और केन्द्रीय करों के लिए 214 करोड़ 64 लाख रूपये का अतिरिक्त अधीनस्थ ऋण, वित्त पोषण एजेंसी बैंकों से ऋण निधि के विरुद्ध 3,496 करोड़ 15 लाख रूपये का अतिरिक्त पीटीए/आंतरिक ऋण, मध्यप्रदेश शासन से राज्य करों के लिए 656 करोड़ 96 लाख रूपये एवं आईडीसीकी लागत के लिए 518 करोड़ 42 लाख रूपये का अतिरिक्त ऋण शामिल है।

### श्रमिक कल्याण से संबंधित योजनाओं के लिए 531 करोड़ 78 लाख रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा श्रमिक कल्याण से संबंधित श्रम विभाग अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के एक अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक कुल 5 वर्षों तक संचालन के लिए 531 करोड़ 78 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार श्रम आयुक्त कार्यालय के संचालन के लिए 57 करोड़ 48 लाख, श्रम कानूनों के कार्यान्वयन के लिए अमला के लिए 289 करोड़ 89 लाख, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए 75 करोड़ 52 लाख, विभागीय परिसंपति के लिए 1 करोड़ 20 लाख, श्रम कल्याण निधि की स्थापना के लिए 95 करोड़, इंदौर में स्थित हायजिन लैब का आधुनिकीकरण के लिए 0.60 करोड़, बाल श्रमिक सर्वेक्षण/पूनर्वास योजना के लिए 4 करोड, बंधक मजदूरों की पुनर्वास योजना के लिए 4 करोड़, नेशनल डेटाबेस अंसगठित श्रमिक के लिए एक करोड़ 25 लाख, प्रवासी श्रमिक आयोग के लिए 0.05 करोड़, असंगठित शहरी/ग्रामीण कर्मकार मंडल की स्थापना के लिए 0.0005 करोड़, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए 0.0005 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी के साथ पूंजीगत मद की विद्यमान योजना श्रम आयुक्त के लिए 1 करोड़ 9 लाख, श्रम कानूनों के कार्यन्वयन के लिए अमला के लिए 0.67 करोड़, औ?द्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए 0.22 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

## नए सिरे से होगी प्रशासनिक सर्जरी

### एक एडीएम, 3 एसडीएम, 7 तहसीलदारों के ट्रांसफर

**भोपाल (नप्र)।** एक एडीएम, तीन एसडीएम और सात तहसीलदार-प्रभारी तहसीलदारों के ट्रांसफर के बाद भोपाल में अब नए सिरे से प्रशासनिक सर्जरी होगी। हालांकि, कुछ नए अधिकारी भोपाल में आए भी हैं, लेकिन उनकी संख्या ट्रांसफर हुए अधिकारियों की संख्या से कम ही है।

सोमवार देर रात राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट आई। जिसमें एडीएम अंकुर मेश्राम को स्टेट सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड में महाप्रबंधक बनाया गया है। वहीं, बैरागढ़ एसडीएम रविशंकर राय को जबलपुर, एमपी नगर एसडीएम एलके खरे को उप सचिव उच्च शिक्षा विभाग, संयुक्त कलेक्टर इकबाल मोहम्मद को निवाड़ी, संयुक्त कलेक्टर विनीत तिवारी को आयुष्मान भारत में सीईओ, गोविंदपुरा एसडीएम भुवन गुप्ता को भोपाल निगम में उपायुक्त बनाया गया है। संयुक्त कलेक्टर राय, इकबाल मोहम्मद और खरे पहले ही पदोन्नत होकर अपर कलेक्टर हो चुके हैं। ऐसे में तीनों को राय को जबलपुर और इकबाल मोहम्मद की निवाड़ी अपर कलेक्टर के पद पद पोस्टिंग की गई है।

भोपाल संभाग आयुक्त कार्यालय में उपायुक्त किरण गुप्ता का भी ट्रांसफर हुआ है। उनकी जगह भारती देवी मिश्रा उपायुक्त के तौर पर पदस्थ की गई हैं।

**तहसीलदार पारे स्टेट गैरेज अधीक्षक-** हुजूर तहसील में पदस्थ आलोक पारे को स्टेट गैरेज में अधीक्षक बनाया गया है। वहीं, दतिया से आए एडीएम महेंद्र सिंह कवचे की पदस्थापना की गई है। परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टर शिवांगी बघेल की पदस्थापना भोपाल में की गई है।

# प्रमुख ठिकानों पर हो सकता है ड्रोन अटैक!

- सरकार का एजेंसियों को अलर्ट-इन जगहों पर सुरक्षा बढ़ाएं
- एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती शुरू, सुरक्षा एजेंसियां हुई सतर्क

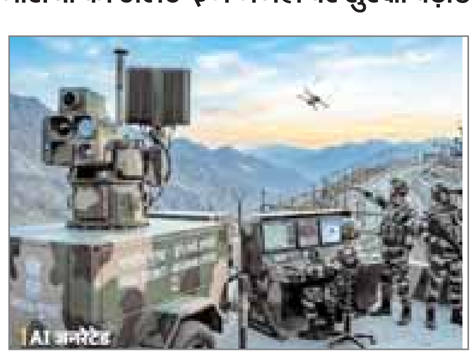


**नई दिल्ली (एजेंसी)।** केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि सीमाओं पर मौजूद महत्वपूर्ण ठिकानों पर दुश्मन ड्रोन हमला कर सकता है। एक अंग्रेजी अखबार की खबर के मुताबिक जहाज और जलमार्ग मंत्रालय के समुद्री सुरक्षा विंग ने जमीन और समुद्री सीमाओं के पास मौजूद महत्वपूर्ण संपत्तियों और ठिकानों पर ड्रोन अटैक को लेकर अलर्ट जारी किया है। मंत्रालय के लेटर में लिखा है- हमें जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने होंगे, खासकर सीमा के पास बने अपने ठिकानों को खतरनाक ड्रोनों से बचाने के लिए एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाने होंगे। दुनिया के मौजूदा हालात को देखकर यह साफ है कि दुश्मन के ड्रोन हमारे जरूरी ठिकानों के कामकाज को ठप कर सकते हैं। इस चेतावनी के बाद सुरक्षा एजेंसियां देशभर के खास ठिकानों को सुरक्षित रखने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने में जुट गई हैं।

### एंटी ड्रोन सिस्टम को जांचने के लिए टीम बनाई

गृह मंत्रालय ने भी सीमा सुरक्षा बल के तहत एक खास कमेटी बनाई है। इस कमेटी का काम भारत के लिए सबसे अच्छे एंटी-ड्रोन सिस्टम को जांचना और पास करना है। सूत्रों ने बताया कि बीएसएफ पाकिस्तान सीमा से सटे पंजाब के इलाकों में इन सिस्टमों को लगाने की तैयारी कर रही है, और इसके लिए बाकायदा ट्रायल भी शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने भी एक टीम बनाई है। इस टीम में रक्षा अनुसंधान संगठन, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एयरपोर्ट अथॉरिटी और बीएसएफ के अधिकारी शामिल हैं, जो देश के महत्वपूर्ण ठिकानों का दौरा कर रहे हैं।

### तमिलनाडु में देश का पहला पोर्ट, जहां एंटी-ड्रोन सिस्टम

तमिलनाडु के थूथुकुडी में वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट मौजूद है। पोर्ट की सिक्योरिटी के लिए फरवरी 2026 में यहां एडवांस एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाया गया। ऐसा सिस्टम अपनाने वाला यह देश का पहला पोर्ट है। इसके लिए बंदरगाह ने सरकारी कंपनी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है।

इस प्रोजेक्ट के तहत रेडियो फ्रीक्वेंसी और रडार पर आधारित एक ऐसा सिस्टम लगाया जा रहा है, जो न सिर्फ दुश्मन के ड्रोन को पहचान लेगा, बल्कि उसे जाम भी कर देगा। यह सिस्टम बंदरगाह के माहौल के हिसाब से तैयार किया गया है जो चारों तरफ यानी 360ए नजर रखेगा।

# अमेरिका-ईरान में पीस डील पर हुए डिजिटल हस्ताक्षर

### 19 जून को होगी औपचारिक डील, खाका हो गया तैयार

**तेहरान/वॉशिंगटन (एजेंसी)।** अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया है कि अमेरिका-ईरान समझौता पूरा हो चुका है और इस पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में औपचारिक हस्ताक्षर होंगे। ट्रम्प ने कहा कि अमेरिकी डेलिगेशन की अगुआई उपराष्ट्रपति जेडी वेंस करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि ट्रम्प, जेडी वेंस और ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ डिजिटल रूप से समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। हालांकि, समझौते का पूरा मसौदा अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। ट्रम्प ने कहा कि दस्तावेज शुक्रवार के बाद जारी किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दोनों देशों के बीच 14 पॉइंट वाला एक शुरुआती मसौदा तैयार हुआ है, जिस पर आगे तकनीकी स्तर की बातचीत होगी। वहीं कुछ रिपोर्टों के मुताबिक ईरान को आर्थिक सहायता के लिए करीब 28 लाख करोड़ रुपए का पैकेज मिल सकता है, हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

# छिंदवाड़ा के मौलाना की घिनौनी हरकत

### जबरन कलमा पढ़ाकर एयरफोर्स अफसर की पत्नी को दरिंदों के चंगुल में फंसाया

**छिंदवाड़ा (नप्र)।** महाराष्ट्र के नागपुर में भारतीय वायु सेना के एक अधिकारी की पत्नी के दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग, जबरन वसूली और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। मामला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का है। इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड छिंदवाड़ा का एक मालौना माना जा रहा है। हालांकि अभी मौलाना की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस के अनुसार, 24 वर्षीय पीड़िता नागपुर में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती है।

### होटल में मुलाकात, फिर बेहोश

पीड़िता का आरोप है कि होटल में बातचीत के दौरान आरोपी ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। पेय पदार्थ पीने के कुछ समय बाद वह बेहोश हो गई। शिकायत के मुताबिक, इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और आपत्तिजनक फोटो व वीडियो बना लिए। जब महिला को होश आया तो उसे घटना की जानकारी मिली।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 20 °c
न्यूनतम 18°c

# सुबह सवेरे

भोपाल ■ बुधवार, 17 जून 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

**संक्षिप्त समाचार**

## सड़क किनारे खड़े युवक को टक्कर मारी, घायल

### नशे में धुत था क्रेटा चालक, बचाने गए युवक को गंभीर चोटें; पुलिस ने दर्ज किया मामला

**भोपाल (नप्र)।** मंडीदीप शहर में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने का मामला सामने आया है। सोमवार देर रात एक सफेद क्रेटा कार ने सड़क किनारे खड़े युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया।प्राप्त जानकारी के अनुसार, फरियादी योगेश विश्वकर्मा (49), निवासी रायल पार्क सिटी मंडीदीप जो भोपाल स्थित एक निजी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं, ने थाना पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 15 जून की रात करीब 10-30 बजे वे अपने दोस्त नवमीत भट्ट के साथ कॉलोनी के गेट के पास खड़े होकर बातचीत कर रहे थे।इसी दौरान एक सफेद रंग की क्रेटा कार तेज रफ्तार में वहां पहुंची। कार चालक, जिसकी पहचान धर्मेन्द्र सिंह राजपूत के रूप में हुई है, कथित रूप से शराब के नशे में था। आरोप है कि उसने आते ही दोनों को गालियां देना शुरू कर दीं।स्थिति बिगड़ते देख नवमीत ने योगेश को पीछे खींचकर बचाने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच आरोपी ने तेज रफ्तार में गाड़ी बढ़ाते हुए नवमीत को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि नवमीत दूर जाकर गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया।

## कांग्रेस में अब पुराने नेताओं की होगी 'घर वापसी'

### पहले गहलोत फिर केसी वेणुगोपाल ने भी कह दी वही बात

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** टीएमसी में टूट के बाद से ही ऐसी चर्चा है कि क्या ममता बनर्जी की कांग्रेस में वापसी होगी। पश्चिम बंगाल में ममता की हार और फिर दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद चर्चा और तेज हुई। सिर्फ ममता बनर्जी की ही पार्टी

नहीं बल्कि शरद पवार की पार्टी को लेकर भी ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। कांग्रेस से अलग हुए गुटों के पार्टी में विलय को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अपने पुराने सदस्यों को पार्टी में वापस लेने की इच्छा जताई है। वहीं केसी वेणुगोपाल ने कहा कि जो कोई भी विश्वास रखता है, वह वापस आ सकता है।

## पहले लालू के लिए व्यवस्था हो तब खाली करेंगे बंगला

### चर्चा में राबड़ी देवी की बिहार सरकार को लिखी चिट्ठी

**पटना (एजेंसी)।** पूर्व सीएम राबड़ी देवी को आवंटित 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने की मियाद 15 जून को पूरी हो चुकी है। भवन निर्माण विभाग ने नोटिस दिया था। अभी तक आवास खाली नहीं हुआ है। इस बीच चर्चा है कि राबड़ी देवी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर अपनी स्थिति बताई

है। कहा यह भी जा रहा है कि एक सप्ताह पहले राबड़ी देवी के सचिव ने पत्र लिखकर कहा था कि कार्यकाल पूर्ण होने तक 10 सर्कुलर रोड आवास में ही रहने दिया जाए। बताया जा रहा है कि अंदरखाने शिफ्टिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। किसी भी समय लालू परिवार 39 हार्डिंग रोड आवास में शिफ्ट हो सकता है।

# परिजनों को फ्लाइट में सफर कराया, 35 लाख रुपये ऑनलाइन गेमिंग में हारी

### 42 लाख का गबन कर भागी थी बैंक कैशियर

**खरगोन (नप्र)।** मध्य प्रदेश के खरगोन में बैंक से 42 लाख रुपये का फ्रॉड करने वाली महिला कैशियर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की ठीबगांव ब्रांच में पदस्थ महिला कैशियर ऋतु गोस्वामी पर 41 लाख 58 हजार 95 रुपये के गबन का आरोप है। महिला लंबे समय से फरार चल रही थी। शुरुआती पूछताछ में आरोपी इस बात की जानकारी सामने आई है कि गबन के करीब 35 लाख रुपये महिला ने ऑनलाइन गेम 'स्टार मेकर' में गंवा दिए हैं।

**पुलिस ने बरामद किया कैश-** पुलिस ने आरोपी महिला के पास से 1 लाख 49 हजार रुपये नकद, तीन मोबाइल फोन और बैंक का आईडी कार्ड बरामद किया है। पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि गबन के पैसों से महिला कैशियर अपने परिवार के साथ घूमने-फिरने और हवाई यात्राओं पर खर्च किया गया। खरगोन पुलिस के मुताबिक, ऋतु किसी लिंक के जरिए 'स्टार मेकर' गेम से जुड़ी थी।

**ऑनलाइन गेमिंग में बड़ी रकम हारी-** पुलिस की पूछताछ में महिला कैशियर ने बताया कि वह ऑनलाइन गेम खेलने की आदी थी। गेम खेलते-खेलते वह बड़ी रकम हार गई।

# नीट री-एग्जाम तक भारत में टेलीग्राम पर रोक

● 21 को परीक्षा, 22 जून तक एप काम नहीं करेगा ● बड़ी सख्ती! मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** भारत सरकार ने नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर भारत में टेलीग्राम मैसेजिंग एप के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मंगलवार को प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी। एनटीए ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 की धारा 69 के तहत टेलीग्राम पर रोक लगाई है। यह रोक 22 जून 2026 तक रहेगी। हालांकि आदेश कब से लागू होगा, इसकी तारीख नहीं दी गई है।

नीट री-एग्जाम 21 जून को होगा। सरकार ने एग्जाम के बाद भी टेलीग्राम को अपना मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया है। यानी

भारत में टेलीग्राम पर पहले से भेजे गए मैसेज 30 जून तक एडिट नहीं हो पाएंगे। एनटीए के मुताबिक कुछ लोग टेलीग्राम का इस्तेमाल परीक्षाओं में पेपर लीक होने के फर्जी सबूत बनाने के लिए करते रहे हैं।

ऐसे मामलों को रोकने और परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। एनटीए ने कहा कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने कई टेलीग्राम चैनल, ग्रुप और बॉट्स को हटवाया है। ये प्लेटफॉर्म नीट उम्मीदवारों को गुमराह करने और पेपर लीक का दावा करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे।

### राज्य पुलिस एजेंसियां भी हैं ऐक्टिव

राज्य पुलिस एजेंसियों ने भी इस तरह की धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई की है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने 9 जून को चेतावनी जारी की थी। वहीं अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया, जो 8 टेलीग्राम चैनलों के जरिए ठगी कर रहा था। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला कि एक अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह ने फर्जी बैंक खातों के जरिए करीब 1.5 करोड़ का लेनदेन किया। गिरोह ने एक महीने में करीब एक हजार मोबाइल नंबरों से संपर्क किया था। एनटीए ने कहा है कि टेलीग्राम पर लगी रोक से लाखों लोग प्रभावित होंगे, जो इसका इस्तेमाल पढ़ाई, नौकरी, निजी बातचीत और जानकारी हासिल करने के लिए करते हैं। एजेंसी ने असुविधा के लिए लोगों से माफी मांगी है।

# बकरियां चराई, पिता के साथ खेतों में काम किया

### 12वीं फेल हुआ छात्र तो कमरे में कैद हुआ, अब आईआईटी में मिली सफलता

**बड़वानी (नप्र)।** मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के एक दूरस्थ आदिवासी गांव के स्टूडेंट ने जहां चाह वहां राह की कहावत को सच साबित कर दिखाया है। 12वीं कक्षा में फेल होने के बाद जिस छात्र ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, वही आज देश के प्रतिष्ठित आईआईटी खड़गपुर में प्रवेश पाकर हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया है।

बड़वानी जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर वरला तहसील के खुटवाड़ी गांव निवासी चेतन सोलंकी ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा में अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग में 1309वीं रैंक हासिल कर आईआईटी खड़गपुर के एग्रीकल्चरल एंड फूड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया है।

**ऑनलाइन पढ़ाई पर किया फोकस-** चेतन की यह सफलता सामान्य नहीं है। कुछ वर्ष पहले वह इंदौर जिले के बेटमा स्थित श्रमोदय आवासीय विद्यालय में पढ़ाई के दौरान 12वीं कक्षा में असफल हो गया था। यह असफलता उसके लिए बड़ा मानसिक झटका साबित हुई। परिवार के अनुसार वह गांव लौट आया और खुद को लगभग एक कमरे तक सीमित कर

लिया। लेकिन उसने हार मानने के बजाय ऑनलाइन पढ़ाई को अपना हथियार बनाया।

**परिवार ने दिया साथ-** चेतन के चाचा ओंकार सोलंकी बताते हैं कि 12वीं में असफल होने के बाद पूरा परिवार उसके साथ खड़ा रहा। उन्होंने उस पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया। परिवार ने उसे समझाया कि यदि आईआईटी नहीं भी निकला तो खेती और अन्य कार्यों में उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन चेतन ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से सबकी सोच बदल दी।

**इंटरनेट की थी दिक्कत-** दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र में इंटरनेट और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की चुनौतियों के बावजूद चेतन ने बिना किसी कोचिंग संस्थान की मदद लिए जेईई जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी की। पढ़ाई के साथ-साथ वह जरूरत पड़ने पर अपने पिता कमल सोलंकी के साथ खेतों में भी हाथ बंटाता रहा।

### कृषि के क्षेत्र में करना चाहता है नवाचार

किसान परिवार से आने वाले चेतन ने इंजीनियरिंग की अन्य शाखाओं के बजाय कृषि अभियांत्रिकी को चुना। उसका मानना है कि उसकी शिक्षा का लाभ सीधे किसानों और खेती-किसानी को मिलना चाहिए। वह भविष्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी बनना चाहता है, लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो कृषि क्षेत्र में नवाचार और विकास के लिए काम करेगा।

## उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने डॉ. अलका गुप्ता के निधन पर व्यक्त किया शोक

**भोपाल।** उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर की प्राचार्य डॉ. अलका गुप्ता के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि डॉ. अलका गुप्ता का निधन दंत चिकित्सा शिक्षा जगत एवं प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है। अपने कार्यकाल में उन्होंने महाविद्यालय के विकास, आधारभूत संरचना के विस्तार, नवीन भवन निर्माण एवं शैक्षणिक सुविधाओं के उन्नयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नेतृत्व में महाविद्यालय में सीटों की संख्या 40-50 से बढ़ाकर 100 किए जाने जैसे ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुए।

## मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 'संपर्क अभियान 2026' को मिली बड़ी सफलता

### 2571 शिविरों में 63 हजार से अधिक उपभोक्ताओं की शिकायतों का मौके पर निराकरण

**भोपाल/ग्वालियर।** बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को उनके घर के नजदीक ही निराकरण करने के उद्देश्य से मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संचालित संपर्क अभियान 2026 को सफलता मिली है। 14 मई से शुरू हुए इस विशेष अभियान के तहत भोपाल और ग्वालियर रीजन के 16 जिलों में व्यापक स्तर पर 2571 विशेष शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 63 हजार से अधिक उपभोक्ताओं की शिकायतों का मौके पर ही त्वरित निराकरण किया गया।

**भोपाल रीजन के वृत्तों में लगे शिविर-** भोपाल रीजन के अंतर्गत 187 शिविर शहर वृत्त भोपाल में आयोजित किए गए जिसमें 4305 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण किया गया, इसके साथ ही बैतुल वृत्त में 230 शिविरों में 7045 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, सीहोर वृत्त में 168 शिविरों में 1616 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, राजगढ़ वृत्त में 184 शिविरों में 1148 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, नर्मदापुरम वृत्त में 176 शिविरों में 7582 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, रायसेन वृत्त में 133 शिविरों में 3,923 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, भोपाल (ग्रामीण) वृत्त में 132 शिविरों में 2277 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, विदिशा वृत्त में 102 शिविरों में 3786 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण एवं हरदा वृत्त में 68 शिविरों में 10054 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण किया गया है।

**ग्वालियर रीजन के वृत्तों में लगे शिविर-** ग्वालियर रीजन के अंतर्गत मुरैना वृत्त में 188 शिविरों में 2070 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, शहर वृत्त ग्वालियर में 154 शिविरों में 2324 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, भिंड वृत्त में 148 शिविरों में 1595 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, गुना वृत्त में 133 शिविरों में 3219 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, ग्वालियर (ग्रामीण) वृत्त में 128 शिविरों में 1498 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, श्योपुर वृत्त में 98 शिविरों में 1497 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, दतिया वृत्त में 91 शिविरों में 3194 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, शिवपुरी वृत्त में 174 शिविरों में 2831 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण एवं अशोकनगर वृत्त में 77 शिविरों में 3086 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण किया गया।

# अब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलेगा कफ सिरप

● सरकार ने दवा खरीद के नियम बदले, नोटिफिकेशन जारी

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** कफ सिरप अब बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खरीदे जा सकेंगे। केंद्र सरकार ने ड्रग्स नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत सिरप को अब उस लिस्ट से हटा दिया गया है, जिसमें दवाएं सीधे दुकान से खरीदी जा सकती हैं। सरकार का कहना है कि इससे सिरप आधारित दवाओं पर निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण मजबूत होगा। साथ ही सिरप निर्माता और विक्रेता को लाइसेंसिंग और क्वालिटी कंट्रोल से जुड़े सख्त नियमों का पालन करना ही होगा। मध्य प्रदेश में अक्टूबर 2025 में दूषित सिरप से 26 बच्चों की मौत हो गई थी। नई व्यवस्था के तहत ड्रग्स रूल्स, 1945 की अनुसूची में बदलाव किया गया है। इस अनुसूची में उन दवाओं को रखा गया था, जिन्हें कुछ नियमों में छूट दी गई थी। अब इस सूची से सिरप को हटा लिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि इस बदलाव से पहले अधिसूचना जारी कर आम लोगों और संबंधित पक्षों से सुझाव और आपत्तियां मांगी थीं।

**टीएमसी विवाद** ओम बिरला ने ममता बनर्जी गुट के सांसदों को बुलाया

# दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला करेंगे लोस स्पीकर

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** टीएमसी के बागी गुट को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला कोई भी फैसला दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही लेंगे। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि लोकसभा स्पीकर के ऑफिस से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले सांसदों के गुट को मेल किया गया है। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा स्पीकर ने इस ग्रुप से मीटिंग के बाद ही बागी सांसदों के गुट को लेकर कोई भी फैसला लेंगे। दूसरी तरफ टीएमसी सूत्रों ने बताया कि लोकसभा स्पीकर के दफ्तर से 15 जून को दोपहर दो बजे अभिषेक बनर्जी को ई-मेल किया गया है। उस समय अभिषेक से ईडी पूछताछ कर रही थी और उनके पास न तो अपने फोन और न ही ईमेल तक पहुंच थी।

● **कीर्ति आजाद को लोकसभा स्पीकर के ऑफिस से आया फोन-** टीएमसी सूत्रों ने बताया कि लोकसभा स्पीकर के दफ्तर से आए ईमेल में अभिषेक को उनसे मिलने के लिए उसी दिन दो घंटे के नोटिस पर चार बजे तक का टाइम दिया गया। टीएमसी सूत्रों ने यह भी जानकारी दी कि अभिषेक बनर्जी को मेल मिलने के करीब एक घंटे बाद टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद को स्पीकर के दफ्तर से ईमेल और अपॉइंटमेंट टाइम की जानकारी देने वाला कॉल आया। उन्होंने बताया कि कीर्ति आजाद खुद लोकसभा स्पीकर के दफ्तर गए और उन्हें जानकारी दी कि अभिषेक बनर्जी सरकारी एजेंसियों की जांच में सहयोग करना चाहते थे।

# टीएमसी पर 'पूरा कब्जा' करने की है तैयारी!

● ऋतुब्रत का दावा-और बढ़ेगी एमएलए की संख्या ● कहा-अब नगर निगम और जिला परिषदों की बारी

**कोलकाता (एजेंसी)।** टीएमसी में बगावत की शुरुआत करने वाले ऋतब्रत बनर्जी ने बड़ा दावा किया है। बनर्जी का कहना है कि विधायकों और सांसदों का समर्थन मिलने के बाद अब उनका गुट धीरे-धीरे पार्टी में बाकी हिस्सों पर भी नियंत्रण हासिल करने की ओर आगे बढ़ेगा। ऋतब्रत को टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था लेकिन विधानसभा के स्पीकर ने उन्हें विपक्ष का नेता नियुक्त किया है। विधायकों के बाद टीएमसी के सांसदों ने बगावत की और 28 में से 20 सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से मिले। बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया में अपने विलय का ऐलान किया था।

**नगर पालिका, नगर निगम, जिला परिषद पर है नजर-** ऋतब्रत बनर्जी ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा, 'एक बार सांसदों-विधायकों का मामला पूरा होने के बाद हम नगर निकायों की ओर बढ़ेंगे, नगर पालिका, नगर निगम, जिला परिषद और कई जिलों के अध्यक्ष भी हमारे संपर्क में हैं। यह संसदीय लोकतंत्र है इसमें संख्या जरूरी है।

### ममता की बैठक में पहुंचे सिर्फ 8 विधायक

ऋतब्रत बनर्जी ने कहा कि ममता ने विधायकों की बैठक बुलाई थी लेकिन आठ ही विधायक वहां पहुंचे। 20 से 22 सांसद उनके खिलाफ हैं, ऐसे में उनके पास क्या बचा है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका गुट राज्य सरकार से लड़ेगा लेकिन अगर सरकार कुछ अच्छा करती है तो हम उसका समर्थन भी करेंगे। इस सवाल के जवाब में कि क्या बागी नेता अभी भी ममता बनर्जी के प्रति वफादार हैं, उन्होंने कहा कि हमने ममता बनर्जी को ऑफर दिया था।

### असली टीएमसी होने का किया दावा

जब उनसे पूछा गया कि क्या उनका गुट खुद के असली टीएमसी होने का दावा पेश करेगा तो उन्होंने कहा, हम ही टीएमसी हैं, क्या असली और क्या नकली दो-तिहाई से अधिक सांसद हमारे साथ हैं, दो-तिहाई से अधिक विधायक हमारे साथ हैं। जरूरत पड़ने पर हम चुनाव आयोग में मिलेंगे। ऋतब्रत बनर्जी ने दावा किया कि बागी विधायकों की संख्या 67-68 तक पहुंच जाएगी। चुनाव में टीएमसी को 80 सीटों पर जीत मिली थी।

# यूपी चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट शुरू

● *5 छोटी पार्टियों पर है असदुद्दीन ओवैसी की नजर*

**लखनऊ (एजेंसी)।** उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी अभी से गंभीरता से जुट चुके हैं।

इस बार वह सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस करने से आगे निकल चुके हैं और उसी तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में जुटी हैं, जैसा अन्य परंपरागत सियासी दल करते हैं। वह मुस्लिम वोटरों के साथ-साथ एक ऐसे जातीय समीकरण को जोड़ने की फिराक में हैं, जो अखिलेश यादव ही नहीं, बीजेपी के जनाधार में भी सेंध लगाने की

कोशिश लगती है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को ही यूपी में बीजेपी को हराने के लिए किसी भी दल के साथ गठबंधन की बात कही है।

## आकाशवाणी भोपाल में शिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ

**भोपाल।** आकाशवाणी भोपाल परिसर में मंगलवार को रेडियो प्रोडक्शन एवं प्रेज़ेंटेशन पर आधारित अनुभवनात्मक शिक्षण कार्यक्रम के तृतीय चरण का शुभारंभ हुआ। इस कार्यशाला का आयोजन भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय प्रसारण एवं प्रबंधन अकादमी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है। उद्घाटन

समारोह में दूरदर्शन भोपाल के क्लस्टर प्रमुख सुदर्शन अंसोलिया एवं आकाशवाणी भोपाल के केंद्र प्रमुख संजीव श्रीवास्तव उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को रेडियो प्रसारण के महत्व, उसकी सामाजिक उपयोगिता तथा जनसंचार के क्षेत्र में उपलब्ध विविध संभावनाओं की जानकारी दी। साथ ही रेडियो माध्यम की तक़नीकी एवं व्यावहारिक बारीकियों से अवगत कराते हुए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम समन्वयक पंकज नागर ने प्रतिभागियों का कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद करते हुए उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला विद्यार्थियों को रेडियो प्रोडक्शन, प्रस्तुतिकरण एवं प्रसारण प्रक्रियाओं की व्यावहारिक समझ विकसित करने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगी। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिभागी विद्यार्थियों को आकाशवाणी के विभिन्न अनुभागों की कार्यप्रणाली, कार्यक्रम निर्माण, रिकॉर्डिंग, संपादन तथा प्रसारण संबंधी प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा। इस दौरान आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम प्रमुख शुभम् तिवारी एवं विविध भारती भोपाल के कार्यक्रम प्रमुख आनंद सिंह उद्दे भी मौजूद रहे।

## नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों को साकार करेगी विद्या भारती की कौशल आधारित शिक्षा

### विद्या भारती की भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रथम वोकेशनल एजुकेशन मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ

भोपाल (नप्र)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, एनसीएफ-2023 तथा एनसीईआरटी के मार्गदर्शन में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा तीन दिवसीय कौशल बोध की मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ पं. सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान ,भोपाल में हुआ। यह कार्यशाला दिनांक 16 से 18 जून 2026 तक रहेगी। कार्यशाला में देश के 11 क्षेत्रों से आए चयनित लगभग 80 प्रतिनिधियों को मास्टर ट्रेनर्स की रूप में तैयार किए जाएंगे। कार्यशाला का उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा में कौशल संस्कृति की पुनर्स्थापना, पंचपदी अधिगम प्रक्रिया आधारित कौशल बोध तथा व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावी रूप से स्थापित करना है। अखिल भारतीय कौशल विकास संयोजक श्री रोहित द्विवेदी ने कार्यशाला की भूमिका प्रस्तुत करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि यह

विषय केवल पुस्तक ज्ञान तक सीमित न रहकर जीवनोपयोगी व्यवहार का अंग बने, यही इस कार्यशाला का उद्देश्य है। साथ ही विद्या भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्री गोविन्द महन्त ने बताया कि कौशल विकास के पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य चल रहा है तथा विद्या भारती के 11 क्षेत्रों से आए मास्टर ट्रेनर्स इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रथम कार्यशाला से देश की अपेक्षाओं की पूर्ति होगी तथा प्रशिक्षित आचार्य अपने-अपने विद्यालयों में इसे प्रभावी रूप से लागू करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष डॉ. रविन्द्र कान्हेरे ने कहा कि देखकर और सुनकर बहुत कुछ सीखा जा सकता है, किन्तु वास्तविक कौशल अभ्यास और अनुभव से ही विकसित होता है। उन्होंने कहा कि तकनीकी एवं कौशल के क्षेत्र में देश में लगभग 15 से 20 वर्षों का अंतराल रहा है, जिसे समन्वित प्रयासों से दूर करना होगा। जितने अधिक कौशल विद्यार्थियों के पास होंगे, रोजगार के अवसर उतने ही बढ़ेंगे और भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों को साकार करने में यह कार्यशाला मील का पत्थर सिद्ध होगी। तीन दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यशाला के अंतिम दिवस प्रतिभागियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे। प्रशिक्षण के माध्यम से तैयार होने वाले मास्टर ट्रेनर्स देशभर के सरस्वती शिशु मंदिरों में कौशल आधारित शिक्षा के प्रसार का कार्य करेंगे।

# अवैध कालोनियों की रजिस्ट्री रोकने का कलेक्टरों को अधिकार नहीं

● *अधिकारों पर सरकार ने चलाई कैंची, न्यायिक या अर्द्धन्यायिक आदेश के बगैर प्रतिबंध लीगली वैध नहीं*

**भोपाल (नप्र)।** अवैध कालोनी के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाने वाले कलेक्टरों के अधिकारों पर शासन ने कैंची चलाई है। कलेक्टरों से कहा गया है कि अवैध कालोनी में रजिस्ट्री रोकने का निर्णय कलेक्टर नहीं ले सकते, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अवैध कालोनी अधिनियम में तय प्रावधानों के आधार पर संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई करने तक ही सीमित है।

रजिस्ट्री पर बिना सक्षम अधिकारी और स्पष्ट न्यायिक और अर्द्धन्यायिक आदेश के बिना प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। इन स्थितियों के बगैर खरीदी बिक्री पर रोक संबंधी आदेश लीगली वैध नहीं है।

वाणिज्यिक कर विभाग ने कलेक्टरों से कहा है कि जहां तक रजिस्ट्री का प्रश्न है तो दस्तावेज का पंजीयन स्वत्व का प्रमाण नहीं बल्कि पक्षकारों के बीच लिखा पढ़ी

के संबंध में मात्र सार्वजनिक साक्ष्य बनाता है।

सभी संभागायुक्तों और कलेक्टरों को लिखे पत्र में कहा गया है कि जिला स्तर पर अवैध कालोनाइजेशन के आधार पर कुछ भूमि की खरीदी बिक्री पर रोक लगाने के साथ उनसे संबंधित दस्तावेज की रजिस्ट्री पर प्रशासकीय रूप से या तो अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगाया गया है या अनापत्ति प्रमाण पत्र या अनुमति पत्र की जानकारी मांगी जा रही है।

प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर विभाग अमित राठौर ने यह पत्र जारी कर कहा है कि ऐसे आदेश या निर्देश के अवलोकन से यह भी साफ हुआ है कि इनमें से अधिकांश में प्रतिबंध के आधार स्वरूप किसी वैधानिक प्रावधान का उल्लेख नहीं रहता है तथा जिन मामले में अधिनियम या नियम का उल्लेख किया भी जाता है तो उनमें रजिस्ट्री पर रोक संबंधी कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं होता है।

### कालोनी विकास नियम भी स्पष्ट नहीं होते

प्रमुख सचिव ने कहा है कि कई पत्रों में मध्यप्रदेश नगरपालिका कालोनी विकास नियम 2021 के नियम का उल्लेख कर रजिस्ट्री पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की शर्त लगाई गई है। यह नियम तय तारीख के पूर्व अस्तित्व में आई अनधिकृत कालोनी के परिप्रेक्ष्य में है। इसलिए रजिस्ट्री पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। **रजिस्ट्री कराने वाले की पहचान तथा रजिस्ट्री की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी-** प्रमुख सचिव राठौर ने कहा है कि पंजीयन अधिनियम 1908 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होने वाले दस्तावेजों के संबंध में स्थिति स्पष्ट है। इस अधिनियम को लेकर काम करने वाले पंजीयन अधिकारी के लिए पंजीयन पूर्व जांच में प्रावधान अधिनियम में व्यवस्था है। इसके अनुसार पंजीयन अधिकारी को रजिस्ट्री कराने वाले की पहचान तथा रजिस्ट्री की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। पंजीयन के लिए पेश किए जाने वाले दस्तावेज के साथ नियमानुसार अपेक्षित दस्तावजों के संबंध में मध्यप्रदेश पंजीयन नियम 1939 के नियम में प्रावधान किए गए हैं। पंजीयन नियम में बताई गई परिस्थितियों में पंजीयन अधिकारी दस्तावेज की रजिस्ट्री इनकार करने में सक्षम है। इसके अलावा अन्य किसी भी आधार पर दस्तावेज के पंजीयन से इनकार करने में पंजीयन अधिकारी वैधानिक रूप से सक्षम नहीं हैं।

## रायसेन, बैतूल में बारिश, 33 जिलों में भी अलर्ट

● **सीहोर में सबसे तेज 56 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चली, कई जगह तापमान में गिरावट, देर रात भोपाल में बारिश**

**भोपाल (नप्र)।** मध्य प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। मौसम विभाग ने भोपाल, जबलपुर समेत 35 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में 50 से 60 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि पूर्वी और मध्य हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं देर रात भोपाल में बारिश हुई।

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, गुना, अशोक नगर, सागर, दमोह, कटनी, छिंदवाड़ा, रीवा, जबलपुर, डिंडौरी,

अनूपपुर, आगर-मालवा, ग्वालियर, मैहर, सतना और सिवनी जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई। प्रदेश में सबसे तेज हवा सीहोर में 56 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चली। भोपाल में 55 किमी प्रतिघंटा, सागर में 52 किमी प्रतिघंटा, ग्वालियर और बैतूल में 43 किमी प्रतिघंटा, आगर-मालवा, अशोकनगर और बड़वानी में 41 किमी प्रतिघंटा तथा विदिशा में 39 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार दर्ज की गई। इसके अलावा गुना में 35 किमी प्रतिघंटा, नर्मदापुरम में 31 किमी प्रतिघंटा और उज्जैन में 30 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चलीं। आंधी-बारिश के चलते कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली।

**जनता को खड़ा कराया तो गुस्सा हो गए शिवराज**

# तुम बैठो, मामा खड़ा रहेगा तुम्हारे लिए

**रायसेन (नप्र)।** मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला है। शिवराज सिंह चौहान सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर थे। रायसेन जिले में आयोजित जन कल्याण शिविर के दौरान शिवराज सिंह चौहान गुस्सा हो गए। हालांकि गुस्से में उन्होंने ऐसी बात कही की लोगों ने जमकर तालियां बजाई और 'मामा' के नारे लगाने लगे।

### क्या है पूरा मामला

दरअसल, जन कल्याण शिविर में शिवराज सिंह चौहान को मंच पर बोलने के लिए बुलाया गया था। इस दौरान मंच से कहा गया कि शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं सभी लोग खड़े होकर ताली बजाएं। जनता से खड़े होकर ताली बजवाने की बात सुनकर शिवराज सिंह चौहान नाराज हो गए। शिवराज सिंह चौहान ने माइक पर ऐसा करने वाले नेता को फटकार भी लगाई।

**ये गलत बात है, बार-बार जनता से खड़े होकर ताली बजवाना-** शिवराज सिंह चौहान ने माइक पकड़ते ही कहा- ये गलत बात है, बार-बार जनता से खड़े होकर ताली बजवाना। मैं इस पर आपत्ति करता हूं। जनता हमारी भगवान है और हम उसके सेवक हैं। बार-बार खड़े होकर ताली बजाने के लिए क्यों कहा जा रहा है। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तुम लोग बैठ जाओ, तुम्हारे लिए मामा खड़ा रहेगा। शिवराज सिंह चौहान की यह बात सुनकर वहां मौजूद लोगों ने जमकर ताली बजाई। शिवराज सिंह चौहान ने कहा- भाइयों और बहनों, अभी मकानों का फिर से सर्वे चल रहा है। हमारा लक्ष्य है कि हर पात्र परिवार को मकान मिले। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि- गरीब इज्जत से अपनी जिंदगी गुजार सके, इसके लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई योजनाएं हैं।

**पंचायतों को सीधे मिलेगी राशि-** उन्होंने कहा कि देशभर में खेत बचाओ अभियान चल रहा है। जिसमें किसानों को बताया जा रहा है कि कौन-सी खाद कितनी देनी है और किस जमीन में कौन-सी फसल, फल या सब्जी बेहतर होगी। विकसित भारत - जी राम जी के तहत मध्य प्रदेश को अगले 9 महीनों के लिए लगभग साढ़े सात हजार करोड़ रुपये दी है। यह राशि सीधे पंचायतों के विकास कार्यों में लगेगी।

## सबसे पहले मप्र हुआ नक्सलमुक्त, प्रधानमंत्री मोदी ने की प्रशंसा : मुख्यमंत्री

**भोपाल (नप्र)।** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पूरे देश में सबसे पहले मध्यप्रदेश ने ही नक्सलवाद को समाप्त किया है। लाल सलाम को आखिरी सलाम करने में मध्यप्रदेश ने बाजी मारी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 11 जून को नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मध्यप्रदेश सरकार के विकास के हर मामले में सदैव अग्रणी रहने की क्रियाशीलता की सराहना की। इस वर्ष बैठक का विषय विकसित भारत @2047 के लिये समावेशी मानव विकास था। पहली बार सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की शासी परिषद् की बैठक में भाग लिया। उन्होंने बताया कि गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए केंद्र और राज्यों की साझी भागीदारी, समन्वित प्रयासों तथा विकास के विभिन्न आयामों पर व्यापक और सार्थक चर्चा हुई। देश के जो क्षेत्र नक्सलवाद से प्रभावित थे, वहां विकास की गति तेज करने पर चर्चा हुई। भविष्य में युवाओं के विकास पर सरकार का विशेष रूप से जोर रहेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी को मध्यप्रदेश आयुष्मान योजना, नदी जोड़ो परियोजनाओं के क्रियान्वयन, पीएम मित्र पार्क निर्माण सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों से भी अवगत कराया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद् की बैठक से पहले मंत्रीगण से अनौपचारिक चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने मंत्रीगण को बीते सप्ताह मप्र सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में मिली विशेष उपलब्धियों की जानकारी दी।

**गिरिबाला बोलीं-**

# वकीलों से मुलाकात का समय बढ़ाएं

### ट्विशा के परिजन को मीडिया में बयान देने से रोकें, कोर्ट ने 30 जून तक बढ़ाई रिमांड

**भोपाल (नप्र)।** एक्ट्रेस-मॉडल ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह और सास सेवानिवृत्त जज गिरिबाला सिंह की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले रिमांड पूरी होने पर मंगलवार को दोनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट के सामने पेश किया गया।

इस दौरान गिरिबाला सिंह ने कोर्ट से कहा कि जेल में उन्हें जो हिंदी और अंग्रेजी अखबार दिए जा रहे हैं, उनमें उनके केस से जुड़ी खबरें काटकर अलग कर दी जाती हैं। उन्हें पूरा अखबार पढ़ने को दिया जाए। साथ ही वकीलों से मुलाकात के लिए निर्धारित 20 मिनट की समय-सीमा समाप्त की जाए। मामले की प्रकृति को देखते हुए कानूनी सलाह के लिए अधिक समय की आवश्यकता है।

गिरिबाला ने यह भी मांग रखी कि उन्हें बेटे समर्थ सिंह के साथ एक ही समय पर अपने वकीलों से मिलने की अनुमति दी जाए। इससे कानूनी रणनीति पर बेहतर समन्वय बन सकेगा।

**ट्विशा की दवाइयों की जब्ती का मेमो भी मांगा-** गिरिबाला सिंह ने अदालत के सामने आपत्ति जताते हुए कहा कि ट्विशा के परिजन और रिश्तेदार मीडिया में लगातार बयान दे रहे हैं। इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर उन्हें सार्वजनिक बयान देने से बचने को कहा जाए। जांच के दौरान ट्विशा की दवाइयां जब्त की गई थीं, लेकिन जब्ती पंचनामा (मेमो) की कॉपी गिरिबाला या समर्थ के वकीलों को नहीं दी गई। ये दिलवाई जाए।

सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह ने सीबीआई द्वारा पेश किए गए

न्यायिक हिरासत बढ़ाने संबंधी आवेदन की कॉपी भी मांगी। कोर्ट के आदेश पर ये उनके वकीलों को दे दिए गए।

**सीबीआई ने कहा- दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट नहीं मिली-** ट्विशा पक्ष के वकील शुभांग दीक्षित ने कहा- सीबीआई ने अदालत को बताया कि दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक एजेंसी को नहीं मिली है। यह रिपोर्ट जांच से जुड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके बाद सीबीआई ने दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ाने की मांग की। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

# बरकतुल्ला ने कहा था- 'इस्लाम और कम्युनिज्म में कोई अंतर नहीं है'

(एल.एस. हरदेनिया)

भोपाल। हमारे देश की आज़ादी का आंदोलन जिन महान व्यक्तियों ने प्रारंभ किया था उनमें मौलाना बरकतउल्ला का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। मौलाना उन लोगों में से थे जिन्होंने महात्मा गांधी से पहले आजादी के आंदोलन की शुरूआत की थी। उन्होंने आंदोलन का झंडा दुनिया के अनेक देशों में लहराया। भारत की आजादी की आवाज सारी दुनिया में बुलंद हो इसलिए उन्होंने राजा महेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में निर्वासित भारत सरकार का गठन किया। इस सरकार के मुखिया महेन्द्र प्रताप सिंह थे और वे स्वयं उसके प्रधानमंत्री बने। आजादी का संदेश सभी देशों में पहुंचे इसलिए उन्होंने अनेक भाषायें सीखीं।

प्रथम महायुद्ध के दौरान मौलाना अपने सहयोगियों के साथ जर्मनी गये और उस देश से आजादी की लड़ाई में सहयोग मांगा। इस दरम्यान उनका संपर्क लाला हरदयाल द्वारा गठित 'गदर पार्टी' से हुआ। गदर पार्टी हथियारबंद क्रांति में विश्वास करती थी। उन्होंने अपनी अंतरिम सरकार जिसका गठन 1915 में किया गया था, उसका मुख्यालय काबुल रखा। उसके लगभग चार वर्ष बाद यह सरकार मास्को चली गई। वहां उनकी मुलाकात सोवियत क्रांति के महान नेता व्लादिमिर लेनिन से हुई। इस मुलाकात के याद स्वरूप मास्को में उनका एक स्मारक बना हुआ है, जिसे मैंने स्वयं देखा है। जब मौलाना ने लेनिन से यह कहा कि इस्लाम व कम्युनिज्म में कोई अंतर नहीं है तो लेनिन ने सुझाव दिया कि वे यह संदेश सोवियत संघ के उन क्षेत्रों में जाकर दें जहां मुसलमान रहते हैं।

प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद अंतरिम सरकार की गतिविधियां कम हो गई, फिर भी मौलाना ने अपना प्रचार कार्य जारी रखा। वे इस उद्देश्य से बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, फ्रांस आदि देशों की यात्रा करते रहे। इस दरम्यान उन्होंने अन्य गुलाम देशों में जारी आज़ादी के आंदोलनों से संपर्क स्थापित किया। इस तरह मौलाना की प्रतिष्ठा दुनिया में एक जाने-माने क्रांतिकारी बतौर फैलती रही। अपने गिरते हुए स्वास्थ्य के बाद भी वे कैलिफोर्निया में गदर पार्टी के सम्मेलन में गए। वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। आज इस बात की आवश्यकता है कि मौलाना की याद में एक स्मारक बने।

ऐसा करने के स्थान पर उनके नाम से बने विश्वविद्यालय का नाम बदला जा रहा है। भोपाल के लोग ऐसा नहीं होने देंगे, यह मेरा विश्वास है।

### नईम 4 दिन की एटीएस रिमांड पर, भोपाल कोर्ट में पेश किए गए दोनों आरोपी

# देश विरोधी गतिविधियों के मामले में फराज को भेजा जेल

**भोपाल (नप्र)।** देश विरोधी गतिविधियों और कथित आतंकी नेटवर्क से जुड़े मामले में गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद फराज और नईम अब्दुल्ला को मंगलवार को विशेष न्यायाधीश डॉ. मुकेश मलिक की अदालत में पेश किया गया।

अदालत ने मोहम्मद फराज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया, जबकि नईम अब्दुल्ला को 4 दिन के लिए एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड की रिमांड पर सौंप दिया।

एटीएस ने अदालत को बताया कि मामले की जांच जारी है और आरोपी नईम से पूछताछ के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। जांच एजेंसी उससे नेटवर्क, डिजिटल संपर्कों, विदेशी कनेक्शन और अन्य संदिग्ध गतिविधियों के संबंध में पूछताछ करेगी। इस मामले में अब तक भोपाल से मोहम्मद फराज, देवबंद से नईम अब्दुल्ला, राजस्थान के अलवर से शाकिर मेव और धार से हाजी अजहर की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं हरियाणा के नूंह से एक संदिग्ध को पूछताछ के लिए भोपाल लाया गया है। एटीएस पूरे नेटवर्क, डिजिटल रिकॉर्ड, विदेशी संपर्कों और आर्थिक लेन-देन की जांच कर रही है।

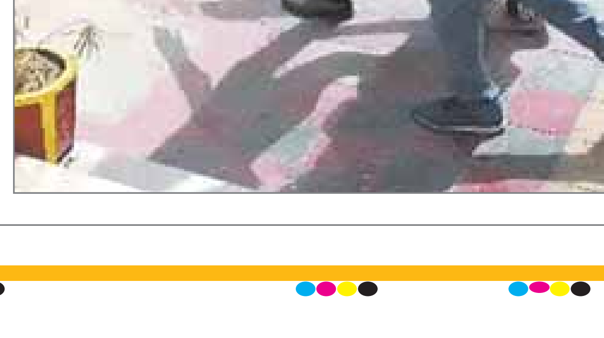

### टेलीग्राम-वाट्सएप ग्रुप से युवाओं को जोड़ने की कोशिश

शुरुआती जांच में सामने आया है कि टेलीग्राम और वाट्सएप ग्रुप्स के जरिए युवाओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। फराज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को जोड़ने और संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े वीडियो साझा करने के लिए ग्रुप बनाता था। वह पिछले करीब चार वर्षों से डिजिटल गतिविधियों में सक्रिय था। अब एटीएस डिजिटल गतिविधियों, विदेशी फंडिंग और पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही है।

संपादकीय

## आरटीआई से खफा सुप्रीम कोर्ट

विगत सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने देश में आरटीआई (सूचना का अधिकार) एक्टिविज्म तथा मप्र में लोकायुक्त को आरटीआई एक्ट से बाहर रखने के संदर्भ में अहम टिप्पणियां कीं। पहली नजर में ये परस्पर विरोधी लगती हैं, लेकिन गहराई से देखें तो वैसा है नहीं, क्योंकि एक मामले में सर्वोच्च अदालत ने आरटीआई के दुरुपयोग गंभीरता से लिया है तो दूसरे मामले में उसने आरटीआई के अधिकार की रक्षा कर जानने के हक को स्वीकार भी किया है। वैसे दो माह पहले भी देश के प्रधान न्यायाधिपति जस्टिस सूर्यकांत ने आरटीआई कार्यकर्ताओं पर तंज कसते हुए उन्हें 'कॉकरोच' कहा था। जिसका नतीजा देश में सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के उदय के रूप में हुआ। यह पार्टी अब सड़कों पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से इस्तीफा मांग रही है। इसी कड़ी में अगली टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की यह है कि आरटीआई एक्टिविज्म अब देश में नया धंधा बन गया है। कोर्ट ने यह टिप्पणी आरटीआई कार्यकर्ता राकेश बहल और उसके सहयोगी की अग्रिम जमानत याचिका के मामले में की और दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। राकेश और राजीव कुमार पर पंजाब के गुरदासपुर में सड़क निर्माण कार्य में बाधा डालने और निर्माण कार्य की निगरानी कर रहे लोगों और मौके पर मौजूद मजदूरों को डराने-धमकाने के आरोप हैं। जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने कहा, 'इन सड़कों के निर्माण की निगरानी करने वाले आप कौन होते हैं? आप कौन सी अथॉरिटी हैं? आपको ये अधिकार किसने दिए हैं।' इससे पहले, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 14 मई को दोनों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। गौरतलब है कि आरटीआई (सूचना का अधिकार) कानून का उपयोग कर सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार को उजागर करने और जनता के प्रति जवाबदेही तय करने को आरटीआई एक्टिविज्म कहा जाता है। यह कानून पूर्ववर्ती यूपीए 1 सरकार 2005 में लाई थी। उद्देश्य यही था कि केन्द्र व राज्य सरकारों के कामकाज में गोपनीयता के आड़ में हो रहे भ्रष्टाचार को जनता के सामने लाया जा सके। इसके तहत सामाजिक कार्यकर्ता या आम नागरिक जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकारी विभागों से महत्वपूर्ण जानकारियां मांगते हैं। बुनियादी तौर पर आरटीआई की शुरुआत सरकारी कामों में होने वाले भ्रष्टाचार को उजागर करने की नीयत से हुई थी। इसके तहत भ्रष्टाचार के कई मामलों का खुलासा भी हुआ, लेकिन जल्द ही इसने नए किस्म की ब्लैकमेलिंग का रूप ले लिया। आरटीआई के नाम पर कुछ लोगों द्वारा इसका गलत इस्तेमाल कर अधिकारियों को डराने या ब्लैकमेल करने के मामले भी सामने आए हैं। निश्चित रूप से यह कानून का दुरुपयोग है और ऐसा करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि सभी आरटीआई कार्यकर्ता गलत हैं। कई जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। कोर्ट द्वारा सभी को एक तराजू में तौलना उचित नहीं है। इसी संदर्भ में एक अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा झटका देते हुए एसपीई लोकायुक्त को आरटीआई के दायरे से बाहर रखने वाली 2011 की अधिसूचना को रद्द कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसी को 'खुफिया या सुरक्षा संगठन' मानकर सूचना के अधिकार से महफूज नहीं रखा जा सकता। भ्रष्टाचार की जांच करने वाली संस्थाओं को इस तरह की छूट नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने इस मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 20 दिसंबर 2021 के फैसले को सही ठहराते हुए उसे बरकरार रखा है। अदालत के इस फैसले के बाद अब मध्य प्रदेश लोकायुक्त (SPE) में पारदर्शी तरीके से RTI के तहत जानकारियां मांगी जा सकेंगी। इसका स्वागत किया जाना चाहिए।

# बहुत अंतर है नेहरू-मोदी और उनके युग में

नजरिया

**अरुण कुमार त्रिपाठी**

**जिन नेहरू की विफलताओं को गिनाने के लिए कई वेबसाइट बनाई गई और संसद से लेकर तमाम पत्र पत्रिकाओं तक में झूठा इतिहास परोसा गया, ऐसे नेहरू से तुलना करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? अगर नेहरू इतने बुरे हैं जितना कि भाजपा और संघ परिवार ने लगातार प्रचारित किया है तो उन्हें इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया जाना चाहिए न कि उनसे तुलना की जानी चाहिए। क्या संघ परिवार का कोई सदस्य यह कहने या सुनने का साहस करेगा कि मोदी जी इक्कीसवीं सदी के नेहरू हैं। कोई अखबार या पत्र या चैनल इस बात को ठकुरसुहाती में भी कहने का साहस नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि नेहरू को महज 12 साल तक प्रधानमंत्री बताने वाला तथ्यहीन और अनैतिहासिक दावा नेहरू पर लगाए जाने वाले संघ परिवार के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर देता है– जैसे कि नेहरू पटेल को दरकिनार करके महात्मा गांधी को खुश करके प्रधानमंत्री बन गए थे। और अगर नेहरू प्रधानमंत्री ही नहीं थे, तो सरदार पटेल आजाद भारत के पहले गृहमंत्री और उपप्रधानमंत्री कैसे कहे जा सकते हैं। फिर तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी न तो भारत के औद्योगिक मंत्री थे और न ही पटेल ने भारत का एकीकरण किया और न ही नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद और डॉ. आंबेडकर ने मिलकर भारत का संविधान बनाया। मोदीजी को खुश करने के चक्कर में भारतीय इतिहास को सिर के बल खड़ा करने का यह प्रयास किसी भी सरकार और व्यवस्था को इतिहास में सीधा खड़ा होने लायक भी नहीं छोड़ेगा।**

हरिवंश राय बच्चन की रचना मधुशाला की कुछ पंक्तियां पंडित जवाहर लाल नेहरू और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कार्यकाल की तुलना पर एकदम सटीक बैठती हैः- 'अपने-अपने युग में सबको अनुपम था अपना प्याला, अपने अपने युग में सबकी अनुपम थी अपनी हाला। लेकिन वृद्धों से जब पूछा, एक यही उत्तर पाया, अब न रहे वे पीने वाले अब न रही वो मधुशाला।' हालांकि तुलना की यह तैयारी 2014 से ही चल रही थी और आखिरकार 2026 में तथ्य और तर्क को दरकिनार करके उसे करने में सरकार और पार्टी और उनकी तमाम मशीनरी जुट गई है।

जब मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे तो एक पत्रिका ने अर्धनारीश्वर की तरह ही मोदी नेहरूश्वर का ग्राफिक कवर पर बनाया था और उनका जोर यह था कि भाजपा मोदी के रूप में नेहरू जैसा आइकन तैयार कर रही है। उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियां भले अलग हों लेकिन आर्थिक नीतियों का ढर्रा वही है। आज मोदीजी के प्रशंसक नेहरू के प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़ने का दावा करते हुए उन्हें बड़ा साबित करने में लगे हुए हैं। ऐसी तुलना न सिर्फ कांग्रेस के पैमाने से अनुचित है, भाजपा और संघ के पैमाने से भी अनुचित है। इस तुलना से भाजपा और संघ का पिछले दो तीन दशक से चलाया जा रहा पूरा आख्यान भरभरा जाता है।

जिन नेहरू की विफलताओं को गिनाने के लिए कई वेबसाइट बनाई गई और संसद से लेकर तमाम पत्र पत्रिकाओं तक में झूठा इतिहास परोसा गया, ऐसे नेहरू से तुलना करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? अगर नेहरू इतने बुरे हैं जितना कि भाजपा और संघ परिवार ने लगातार प्रचारित किया है तो उन्हें इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया जाना चाहिए न कि उनसे तुलना की जानी चाहिए। क्या संघ परिवार का कोई सदस्य यह कहने या सुनने का साहस करेगा कि मोदी जी इक्कीसवीं सदी के नेहरू हैं। कोई अखबार या पत्र या चैनल इस बात को ठकुरसुहाती में भी कहने का साहस नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि नेहरू को महज 12 साल तक प्रधानमंत्री बताने वाला तथ्यहीन और अनैतिहासिक दावा नेहरू पर लगाए जाने वाले संघ परिवार के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर देता है- जैसे कि नेहरू पटेल को दरकिनार करके महात्मा गांधी को खुश करके प्रधानमंत्री बन गए थे। और अगर नेहरू प्रधानमंत्री ही नहीं थे, तो सरदार पटेल आजाद भारत के पहले गृहमंत्री और उपप्रधानमंत्री कैसे कहे जा सकते हैं। फिर तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी न तो भारत के औद्योगिक मंत्री थे और न ही पटेल ने भारत का एकीकरण किया और न ही नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद और डॉ. आंबेडकर ने मिलकर भारत का संविधान बनाया। मोदीजी को खुश करने के चक्कर में भारतीय इतिहास को सिर के बल खड़ा करने का यह प्रयास किसी भी सरकार और व्यवस्था को इतिहास में सीधा खड़ा होने लायक भी नहीं छोड़ेगा। दोनों नेताओं के स्वभाव और युग में जमीन आसमान का अंतर है और उसे खुले दिलो-दिमाग से देखने पर ही दोनों के साथ न्याय किया जा सकेगा। जाहिर सी बात है कि नेहरू एक संपन्न परिवार में पैदा हुए थे और मोदी सामान्य परिवार में। पर इसमें उन दोनों का कोई दोष नहीं है और न ही इस आधार पर किसी की आलोचना करने का या किसी को छोटा बताने का कोई औचित्य बनता है।

मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। जन्म से उसे थोड़ी बहुत मदद मिलती है लेकिन अच्छे और ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले सारे लोग बड़े काम नहीं कर पाते, बड़े पद पर भले ही पहुंच जाएं। यही बात सामान्य परिवार में पैदा होने वाले लोगों के लिए भी सही है। निश्चित तौर पर सामान्य परिवार में पैदा होने वाले का संघर्ष बड़ा होता है लेकिन इतिहास में वैसे लोग भी सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे हैं और अपना राज्य तक कायम किया है। लोकतांत्रिक आदर्शों के मुताबिक़ महानता इस बात में है कि देश और समाज के लिए आप का योगदान क्या रहा और आप ने अपने को कितना वर्गांतरित या डिक्लास किया। जाहिर सी बात है कि मोदीजी को डिक्लास करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन नेहरू ने गांधी के प्रभाव में अपने को डिक्लास किया। उनके इन प्रयासों से उनके पिता और देश के बड़े वकील मोतीलाल नेहरू थोड़े परेशान भी रहते थे।

नेहरू की पढ़ाई-लिखाई और उनकी बौद्धिक अभिरुचि मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी में कहीं से नहीं दिखती। न तो उन्हें 'डिस्कवरी ऑफ़ इंडिया', 'विश्व इतिहास की झलक' और 'पिता के पत्र-पुत्री के नाम' जैसे ग्रंथ लिखने की ज़रूरत है और न ही अभिरुचि और न ही बौद्धिक बेचैनी। मोदी जी ने 'एग्जाम वारियर' जैसी किताब लिखी है और उनके 'मन की बात' को भी प्रकाशित किया गया है। लेकिन देश की आजादी के लिए तकरीबन एक दशक तक जेल में बिताने वाले नेहरू का रिकॉर्ड मोदी जी कैसे तोड़ेंगे? अगर विनायक दामोदर सावरकर को छोड़ दिया जाए तो हिंदुत्व विचार के किसी नेता के खाते में इतनी लंबी जेल यात्रा नहीं है। नेहरू और कांग्रेस पार्टी पर एकहद तक भारत के विभाजन का दोष भी जाता है लेकिन उन्हें इस बात का श्रेय भी जाता है कि उन्होंने एक टूटे हुए देश के बाक़ी बचे हिस्से को जोड़ने संवारने और बनाने का काम किया। 'हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के', शायद यह गीत उन्हीं पर लिखा गया था। नेहरू को चीन से विश्वासघात मिला और मिला देश को पराजय का गहरा जख्म, जिससे नेहरू उबर नहीं पाए और आखिरकार चीन के आक्रमण के एक साल बाद यानी 1964 विदा हो गए। लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से उन्होंने औपनिवेशिक वर्चस्व के विरोध में दुनिया में एक नई चेतना का संचार किया और उसे नेतृत्व दिया। इस नाते नेहरू का अमेरिका से लेकर सोवियत संघ तक गहरा सम्मान था। नेहरू ने भारत और दुनिया के कई देशों को औपनिवेशिक वर्चस्व से निकाला था और वे विऔपनिवेशीकरण के वैश्विक अभियान के अगुआ था, इसीलिए भारत के आजाद होने के बाद दुनिया के कम से कम सौ देश औपनिवेशिक गुलामी से आजाद हुए थे। जबकि मोदी जी ने भारत की संप्रभुता को अमेरिका जैसे वर्चस्ववादी देश के सामने झुका दिया। एक तरह से देखें तो भारत महाशक्तियों के औपनिवेशीकरण अभियान के सामने कोई बाधा नहीं है। न ही वह किसी देश को इस चंगुल से बचाने के लिए इच्छुक और योग्य दिखता है। नेहरू ने 1930 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ही नहीं पेश किया, उन्होंने संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य के तौर पर संविधान का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया और उद्देशिका भी आखिर में पेश की। नेहरू के नेतृत्व में ही भारत को धर्मनिरपेक्ष संविधान मिला और उसी नाते भारत अब तक एकजुट है। जबकि मोदी जी के नेतृत्व में सबसे कमजोर धर्मनिरपेक्षता का ढांचा ही हुआ है और ऐसी नीतियों ने भारत को भीतर से तोड़ा है। मोदी की सफलता निजी और संघ परिवार की सफलता है जबकि नेहरू की सफलताएं देश समाज और दुनिया की सफलताएं थीं।

नेहरू और मोदी की इतनी तुलना भी करने का औचित्य नहीं था लेकिन मोदी जी के भक्तों ने माहौल ही ऐसा निर्मित किया है कि कुछ न कुछ कहना मजबूरी बन जाती है। लेकिन असली सवाल यह है कि मोदी जी और उनके भक्त स्वाधीनता संग्राम का वह आर्थिक रूप से विपन्न, राजनीतिक रूप से गुलाम लेकिन बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध दौर कहां से लाएंगे? तिलक, गांधी, पटेल, मौलाना, सुभाष, टैगोर, भगत सिंह, आचार्य नरेंद्र देव, सरोजिनी नायडू, राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण, ईएमएस नंबूदिरीपाद, डॉ. राममनोहर लोहिया जैसे लोग बार-बार नहीं आते। नेहरू उनके युग में पैदा हुए थे। क्या मोदी जी नेहरू की तरह अपने युग में वैसे लोगों की सोहबत पा सकते हैं? क्या वे उनसे वैचारिक संवाद करने को तैयार हैं? वैसे लोग मानव इतिहास में उन विशेष स्थितियों में उत्पन्न होते हैं जिसका जिक्र अर्नाल्ड जे. टायन्बी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'स्टडी ऑफ़ हिस्ट्री' में किया है।

मानव इतिहास में कई बार ऐसा अद्वितीय नेतृत्व संकट के समय पैदा होता है और खुशहाली के समय नदारद रहता है। कुल मिलाकर दोनों व्यक्ति और दोनों युग एकदम भिन्न हैं और उनकी तुलना अनुचित है।

# प्रकृति के सम्यक उपयोग की ओर लौटने की जरूरत

पर्यावरण

**कुमार सिद्धार्थ**

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

पिछले सात दशक में पर्यावरण को लेकर देश में जबर्दस्त जागरूकता बढ़ी है और पर्यावरण के हर आयाम पर नीतिगत रूप से काम करने की प्रक्रिया भी संचालित की गई है। जंगल बचाने से लेकर नदियों को साफ करने तक, प्रदूषण रोकने से लेकर जैव विविधता के संरक्षण तक अनेक योजनाएं बनाई गईं। लेकिन समग्र रूप से पर्यावरण का आकलन करें तो यही लगता है कि विकास की तेज दौड़ में प्रकृति ने सबसे ज्यादा कीमत चुकाई है। आजादी के बाद सड़कों, सिंचाई परियोजनाओं, बांधों, उद्योगों और शहरों के विस्तार ने देश को आधुनिक विकास की दिशा में जरूर आगे बढ़ाया, लेकिन इस विकास के लिए जल, जंगल और जमीन का जिस तरह इस्तेमाल हुआ, उसके दुष्परिणाम अब सामने आने लगे हैं।

आजादी के शुरुआती दशकों में विकास का अर्थ था- सड़कें, कारखाने, बड़े बांध और बिजली परियोजनाएं। इसके लिए बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए। जंगलों की जगह सड़कें और बस्तियां बसती गईं। खनन, उद्योग और निर्माण कार्यों के लिए वनभूमि का लगातार हस्तांतरण होता रहा। जंगल केवल लकड़ी या वनोपज का स्रोत नहीं होते, वे वर्षा, मिट्टी, जल और जीवन का आधार होते हैं। लेकिन विकास की हमारी अवधारणा लंबे समय तक इन्हें संसाधन भर मानती रही। इसका नतीजा यह हुआ कि जंगलों का दायरा सिकुड़ता गया और पर्यावरणीय संतुलन कमजोर पड़ने लगा।

भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्टें बताती हैं कि देश में हरित आवरण बढ़ाने के प्रयास जरूर हुए हैं, लेकिन प्राकृतिक घने जंगलों की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के मुकाबले वन और हरित आवरण का अनुपात अभी भी उस लक्ष्य से कम है, जिसकी कल्पना राष्ट्रीय वन नीति में की गई थी। वर्ष 1988 की वन नीति में कहा गया था कि देश के एक तिहाई भू-भाग पर जंगल होने चाहिए और पर्वतीय क्षेत्रों में यह अनुपात दो तिहाई होना चाहिए। लेकिन आज भी हम इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए हैं। वृक्षारोपण के अभियान जरूर चलाए गए, पर यह भी गौर करने वाली बात है कि लगाए गए पेड़ों में कितने बचे और वे प्राकृतिक जंगलों की तरह जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन देने में कितने सक्षम हुए।

जंगलों की इस कटाई का असर केवल पेड़ों तक सीमित नहीं रहा। वर्षा चक्र प्रभावित हुआ, मिट्टी का कटाव बढ़ा, नदियों का स्वभाव बदला और जल संकट गहराने लगा। पहले गांवों में चौमासे के पानी को पूरे साल के लिए बचाकर रखने की कुआं, तालाब, बावड़ी और जल-संचयन की समृद्ध परंपरा थी। पानी स्थानीय स्तर पर जमीन में समाता था और भूजल का संतुलन बना रहता था। लेकिन आधुनिक विकास के साथ इन परंपरागत प्रणालियों की उपेक्षा शुरू हो गई। नहरों का जाल बिछाने के लिए नदियों को बांधा गया। बांधों के साथ बिजली उत्पादन का तर्क भी जोड़ा गया। फिर भी जब सिंचाई की कमी रह गई तो नलकूपों का सहारा लिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि भूजल का अत्यधिक दोहन शुरू हो गया। आज देश के अनेक हिस्सों में भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और पानी का संकट जीवन की बड़ी चुनौती बन चुका है।पर्यावरण की इस गिरती स्थिति की आहट बहुत पहले सुनाई देने लगी थी। 1970 के दशक में उत्तराखंड के चमोली में चिपको आंदोलन शुरू हुआ। गांव के लोग अपने जंगलों को कटने से बचाना चाहते थे, क्योंकि उनकी आजीविका, उनका भविष्य और उनका जीवन उन्हीं जंगलों पर निर्भर था। इसी तरह नर्मदा घाटी में बड़े बांधों के दुष्प्रभाव सामने आए तो वहां भी लोगों ने आवाज उठाई। केरल की शांत घाटी हो, पश्चिमी घाट के जंगल हों, बस्तर का आदिवासी क्षेत्र हो या समुद्रतटीय इलाके–देश के अलग-अलग हिस्सों में लोगों ने अपने-अपने स्तर पर प्रकृति बचाने की लड़ाई लड़ी। इन आंदोलनों ने देश को यह समझाया कि पर्यावरण केवल पेड़ों और नदियों का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह मनुष्य, समाज, संस्कृति और भविष्य का प्रश्न भी है।

सही बात है कि औद्योगिकीकरण और बड़े विकास मॉडल के जितने लाभ गिनाए गए थे, उतने वास्तव में नहीं दिखे। अनेक बड़ी घाटी परियोजनाओं के लिए हजारों परिवार उजाड़े गए, लेकिन उनके पुनर्वास की समस्याएं आज तक पूरी तरह नहीं सुलझीं। बड़ी परियोजनाओं ने क्षेत्रीय संस्कृति, जीवन-पद्धति और स्थानीय समाज को भी प्रभावित किया। यह भी सच है कि बड़े बांधों और भारी निर्माण कार्यों के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों का आकलन हमेशा गंभीरता से नहीं किया गया। विकास की चमक में प्रकृति और मनुष्य के बीच के रिश्ते को अक्सर नजरअंदाज किया गया।

आज पर्यावरण संकट का सबसे बड़ा चेहरा ग्लोबल वार्मिंग के रूप में सामने है। मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। कहीं भीषण गर्मी पड़ रही है, कहीं अचानक बाढ़ आ रही है, कहीं लंबे सूखे की मार है तो कहीं चक्रवात और जंगल की आग जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में देश ने असामान्य तापमान, बेमौसम बारिश और प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता को करीब से देखा है। गर्मी के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और शहरों से लेकर गांव तक इसका असर महसूस किया जा रहा है।लेकिन हमें केवल ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, लोकल वार्मिंग को भी पहचानने की जरूरत है। हिमालय इसका बड़ा उदाहरण है। बदरीनाथ, केदारनाथ जैसे तीर्थ, हिमशिखर, हिमनदियां और बर्फीली चोटियां हमारे प्राकृतिक वैभव का हिस्सा हैं। पहले इन इलाकों में सीमित संख्या में लोग पहुंचते थे। वे परंपरागत साधनों और स्थानीय आवासों का उपयोग करते थे और लौट जाते थे। इससे वहां के पर्यावरण पर दबाव न्यूनतम रहता था। लेकिन सुविधाओं के विस्तार और पर्यटन के बढ़ते दबाव ने इन क्षेत्रों का स्वरूप बदल दिया है। आज लाखों यात्री हर साल इन इलाकों में पहुंचते हैं। सड़कों, होटलों, पार्किंग, वाहनों और निर्माण गतिविधियों का असर वहां के सामान्य तापमान, हिमनदों और नदियों के परितंत्र पर पड़ रहा है। हिमालय की संवेदनशीलता को देखते हुए हाल के वर्षों में आई आपदाओं ने यह चेतावनी भी दी है कि प्रकृति की सीमाओं की अनदेखी भारी पड़ सकती है।

शहरों में भी पर्यावरण की स्थिति कम चिंताजनक नहीं है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, कचरे का संकट और बढ़ती गर्मी ने शहरी जीवन को कठिन बना दिया है। महानगरों में हरियाली घट रही है और सीमेंट-कंक्रीट का फैलाव बढ़ रहा है। वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसके कारण हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। गर्मियों में शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण इलाकों से कई डिग्री ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। यह भी लोकल वार्मिंग का ही एक रूप है।हाल के वर्षों में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कुछ सकारात्मक पहलें भी हुई हैं। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। जल संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, कचरा प्रबंधन और पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली को लेकर नई पहलें की जा रही हैं। लेकिन यह भी सच है कि केवल योजनाओं और कानूनों से पर्यावरण नहीं बचाया जा सकता, जब तक समाज की जीवनशैली और विकास की सोच में बदलाव न आए।गांधी जी कहते थे कि प्रकृति हर एक की जरूरत तो पूरी कर सकती है, पर लालच नहीं। यह गूढ़ बात आज पहले से ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। पिछले 75 साल में विकास की हमारी अवधारणा प्रकृति के अधिकतम दोहन पर केंद्रित रही है। अब समय आ गया है कि हम उन परंपरागत भारतीय व्यवस्थाओं को फिर से याद करें, जिनमें जल का संरक्षण था, जंगलों के प्रति सम्मान था और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीने की समझ थी। हमें प्रकृति के सम्यक उपयोग की अवधारणा को फिर से बढ़ाना होगा। विकास जरूरी है, लेकिन ऐसा विकास जो पर्यावरण को नष्ट करके नहीं, बल्कि उसके साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़े। क्योंकि जल, जंगल और जमीन केवल आज की जरूरत नहीं, आने वाली पीढ़ियों की भी धरोहर हैं। यही समझ देश के पर्यावरण के सच्चे विकास का आधार बन सकती है।

# मानसून - कम सून

सामयिक

**सुरेश उपाध्याय**

लेखक साहित्यकार हैं।

अब तो आ भी जाओ मानसून, जल्दी आओ, कम सून। मयूर और मन दोनों तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 140 करोड़ जन की आस और विश्वास हो तुम। तुम आओ तो रेडियो और चित्रहार का मिजाज भी बदले। बरखा बहार आई/ रस की फुहार लाई से लेकर तेरी दो टिक्या की नौकरी में/ मेरा लाखो का सावन जाए जैसे सदाबहार तराने फिजा को और खुशगवार कर दे, जीवन में उमंग व उत्साह भर दे। दो ज्येष्ठ (अधिकमास) से तपी धरती में पड़ी दरारें तुम्हारी बाट जो रही है। कूलर व वातानुकूलन यंत्र से गर्मी व पसीने पर विजय प्राप्त करने के जतन ने आमजन को बिजली बिल से त्रस्त कर दिया है। आओ और सौंधी मिट्टी की सुगंध से धरती को सराबोर कर दो, मंत्रमुग्ध कर दो। धरा को हरियाली की चादर ओढ़ा दो। सूखी नदियों और रीते जल स्त्रोतों को लबालब कर दो। खरीफ की फसल तुम्हारे प्रत्यक्ष भरोसे है तो रबी भी परोक्ष तुम्हारे ही सहारे है। जीवन की आस हो तुम, जीवन की प्यास हो तुम।

आते–आते तुम्हारा ठीठक जाना, रास्ते में रुक जाना परेशानी का सबब बन रहा है। आओ कि सबने स्वागत की पूरी तैयारी कर ली है। ड्रीम गर्ल के गालो व अमेरिका से अच्छी सडको के नाम पर कांक्रीट – सीमेंट की जिन सड़कों को हमने गलतियां सुधारने के लिए उखाड़ दिया था या अन्यान्य कारणों से गड्ढे पड़ गए थे, डामर के पेच वर्क से हमने उन्हें सुधार दिया है। एक तरह से उन्हें नजर लगने से बचाने के लिए काला टीका लगा दिया है। टपकती छतों की वाटरप्रूफिंग भी हो गई है तथा टूटे –फूटे कवेलू भी बदल दिए हैं। नदियों व तालाबों की गाद निकालने, उनको गहरे करने, अतिक्रमण हटाने के समाचार व चित्र भी हमें दिखाए गए हैं। नालों की टेपिंग, सीवरेज की सफाई, स्ट्राम वाटर लाइन के कार्य पूर्ण करके जलभराव न होने के प्रति भी हमें आश्वस्त किया जा चुका है।

हम स्वीकार (कंफेस) करते हैं – हमने प्रकृति का अत्यधिक दोहन किया है, उसके साथ खिलवाड किया है, वनो व पेडो की अंधाधुंध कटाई की है, पहाड़ों की छाती छलनी कर दी है, नदियों, तालाबों व जलस्त्रोतों को गंदा / प्रदूषित किया (सीवरेज, औद्योगिक अपशिष्ट आदि से) है, जल संरचनाओं व उनके जलभरण क्षेत्रों में अतिक्रमण किया है। हवा, पानी, ध्वनि , प्रकाश सहित पर्यावरण व पारिस्थितिकी का कोई भी क्षेत्र प्रदूषण रहित हमने नहीं छोड़ा है। नाभीकीय, रासायनिक, जैविक, मिसाइलों, अत्याधुनिक हथियारों व ड्रोनों के विनाशकारी प्रभावों को देखने के बाद भी हमने कोई सीख नहीं ली है। प्रकृति पूजा की परम्परा का पालन तो हम कर रहे हैं लेकिन उसके संवर्धन, संरक्षण व परिवर्धन के लिए हमारे प्रयास न पर्याप्त हैं, न गम्भीर। बड़े स्तर पर इनका कारण विनाशकारी विकास नीतियां रही हैं तो ऐसी नीतियों / कार्यक्रमों पर प्रभावी प्रतिरोध न उत्पन्न करने की जिम्मेदारी तो हमारी है ही।

इन स्थितियों पर होने वाले विमर्श, चर्चाएं, छोटे–छोटे समूहों व व्यक्तिगत प्रयास आशा की किरण हैं। सरकारो के स्तर पर भी चर्चाएं व कार्यक्रम बन रहे हैं। लेकिन एक महादेश व विराट भूभाग के लिए वृहद, वैज्ञानिक व प्रभावी नीतियों व कार्यक्रम तथा उसमें निरंतरता की दरकार है।

पराली जलाकर ही सही किसानों ने खेतों को तैयार किया है। छोटे स्तर पर ही सही जल स्त्रोतों पर थोड़ा बहुत काम किया गया है। जल पुनर्भरण के लिए लोगों ने घरेलु नलकूपों पर भी गड्ढों व फिल्टर केप्सूल के माध्यम से प्रयास किए हैं।

शीघ्र आओ मानसून, कम सून मानसून इन प्रयासों का मान रखो। तुम्हारी बेरुखी पर टोने – टोटके यथा मेंढक–मेंढकी का ब्याह, मंदिरों में पानी भरने, उज्जैनी (वन भोजन) के जतन न करना पड़े, तो अच्छा ही है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

**प्रधान संपादक**
उमेश त्रिवेदी
**कार्यकारी प्रधान संपादक**
अजय बोकिल
**संपादक (मध्यप्रदेश)**
विनोद तिवारी
**वरिष्ठ संपादक**
पंकज शुक्ला
**प्रबंध संपादक**
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

# पुचका-पुचका लिखा करो

व्यंग्य

**जवाहर चौधरी**

लेखक व्यंग्यकार हैं।

'देखा, आप एक समझदार आदमी हो। कई बार लोग समझदार होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो हैं। आप भी हैं, लेकिन आपको पता नहीं हैं।' परम जी ने हमदर्दी जताते हुए कहा। मेरे जीवन के वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे समझदार कहा है। जीवन संगिनी से मुझे हमेशा उम्मीद रहती है लेकिन उनका कहना है कि फालतू बकवास मैं नहीं करती हूँ। शुरू में समझाया कि भइ तुमसे शादी की है, इसी बात पर एक बार कह दो। लेकिन उनका मानना है कि वह तुम्हारी समझदारी नहीं, मेरी नासमझी थी। यही वजह है कि जब परम जी ने समझदार कहा तो मुझे उनकी ही समझदारी पर शंका हो गई। बावजूद इसके शराफत का तकाजा है कि मुझे उनका आभारी हो जाना चाहिए। आज के इस गलाकाट जमाने में किसी दूसरे को समझदार मान लेना और कह देना बहुत गैर मामूली घटना है। लोकतंत्र में हर पाँच साल में जनता को समझदार कहकर मूर्ख बनाने की आदर्श परंपरा रही है। मुझे लग रहा है कि हो ना हो परम जी किसी राजनीतिक दल के दबे छुपे कार्यकर्ता हैं। वोट का समय होता तो समझदार कहने के बाद मुझे वोट मांग लेते, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी कुछ ना कुछ तो मांगेंगे। आज के जमाने में यूं ही कोई किसी को फिरी फुग्गे में समझदार नहीं कह देता है।

'जी साहेब, हौसला अफजाई के लिये आपका आभारी हूँ। वैसे मुझे मालूम है कि मैं समझदार हूँ। वाइफ भी कहती हैं, लोग भी कहते ही रहते हैं। फिर भी धन्यवाद आपका।' हमने अपने हिसाब से गरिमावर्धक उत्तर दिया।

'साहेब नहीं श्रीमान कह सकते हैं।... आप लेखक हैं ना?'

'हाँ श्रीमान हम लेखक हैं.... और आप?'

'हम मार्गदर्शक हैं।'

'आप तो जवान हैं! फिर मार्गदर्शक कैसे!'

'हम साहित्यिक मोर्चा के मार्गदर्शक हैं। आप लोगों को कैसे और क्या लिखना चाहिए इसकी दिशा देना हमारा काम है।'

'साहित्यिक मोर्चा! मतलब साहित्य में गहरी रूचि होगी आपकी?'

'रूचि वुची कुछ नहीं, काम करना है हमें तो... देश सेवा। किसी भी मोर्चे पर खड़ा कर दो हम सब सम्हाल लेते हैं।... आज आपको दिशा देने के लिये आए हैं।' कहते हुए उन्होंने सामने रखी कुर्सी पकड़ी। बोले -- 'देखिए आपका लिखा देखते हैं हम। आपको सुधरना होगा।'

'सुधरना होगा!! कैसे !'

'दुनिया में कितना कुछ हो रहा है उस पर नजर रखते हो!?... नहीं ना। फिर ये क्या, कभी महंगाई, कभी बेरोजगारी, कभी भ्रष्टाचार!! लोग पढ़ते हैं तो बहुत दुःखी होते हैं। पाठकों को दुःखी करने के लिये लिखना अच्छी बात नहीं है। साहित्य ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को खुशी मिले। उनका मनोरंजन हो। लगे कि अमन चैन है चारों तरफ। कोई पढ़े तो गार्डन गार्डन हो जाए, उसे लगे कि रेगिस्तान में फूल खिल रहे हैं। कोई आदमी दिनभर मेहनत करके शाम को राहत के लिए अख़बार उठाता है और 'तुम' गैस और पेट्रोल का भाव दिखा देते हो! सोचो उस पर क्या गुजरती होगी!!... 'तुमको' अपने आप समझ जाना चाहिए।' परम जी ने करीब करीब नाराज होते हुए कहा।

'जो जनहित में होता है वही लिखना होता है जी....।'

'जनहित हमारी चिंता है, 'तुमको' करने जरूरत नहीं है। आइंदा ठीक से लिखिये। कोई असावधानी नहीं हो।'

'ठीक से मतलब कैसे?'

'पुचका - लिखो। पुचका समझते हो?... पानीपुरी खाई है ना? पूरी को पुचका कहते हैं। कैसा दीखता है बड़ा बड़ा, उसमें होता कुछ नहीं है सिवा इमली और नमकीन पानी के। लेकिन मजा देखो कितना आता है। पुचका लेखन करो देशभक्त बनो। ... अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, प्रशिक्षण करवा देते हैं।'

राजमाता जीजाबाई

गिरीश जोशी

(संस्कृति अध्येता और स्तंभकार)

# जीवन, व्यक्तित्व और राष्ट्र निर्माण में योगदान

**जिजाबाई ने अपने जीवन में सत्ता संघर्ष, विश्वासघात, युद्ध और पारिवारिक त्रासदियों को निकट से देखा। उनके पिता लखूजी जाधव की हत्या ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला। इसी अनुभव ने उनमें स्वतंत्र राज्य की आवश्यकता का भाव अधिक प्रबल किया। उस परिस्थिति में जब स्वराज स्थापित करने का विचार भी किसी के मन में नहीं उठता था तब शाहजी राजे और जीजामाता ने स्वराज का स्वप्न देखा।**

## जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि

लखूजी जाधवराव तत्कालीन दक्कन के प्रमुख मराठा सरदारों में गिने जाते थे उनके यहाँ जिजाबाई का जन्म लगभग 1598 ई. में सिंदखेड़ में हुआ था। 17वीं शताब्दी का दक्कन राजनीतिक अस्थिरता से भरा हुआ था। मुगल साम्राज्य दक्षिण की ओर विस्तार कर रहा था। लखुजी, निजामशाह के विश्वसनीय सरदार थे। जीजाबाई का विवाह शाहजी राजे के साथ हुआ। सन् 1629 में निजामशाह ने राजद्रोह के संदेह में लखुजी जाधवराव के साथ उनके तीन पुत्र अचलोजी,रघुजी और यशवंतराव चारों की हत्या कर दी। इस घटना से पूरा हिंदुस्तान दहल उठा। इस घटना से शाहजी राजे भी अत्यंत उद्वेलित हुए और निजामशाह की सेवा छोड़कर विद्रोही हो गए।

जिजाबाई ने अपने जीवन में सत्ता संघर्ष, विश्वासघात, युद्ध और पारिवारिक त्रासदियों को निकट से देखा। उनके पिता लखूजी जाधव की हत्या ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला। इसी अनुभव ने उनमें स्वतंत्र राज्य की आवश्यकता का भाव अधिक प्रबल किया। उस परिस्थिति में जब स्वराज स्थापित करने का विचार भी किसी के मन में नहीं उठता था तब शाहजी राजे और जीजामाता ने स्वराज का स्वप्न देखा। इस स्वराज के निर्माण के लिए अपना जीवन दाँव पर लगा कर प्रयत्न भी किया। मालोजीराजे के समय से ही पुणे की जागीर उनके पास थी। शाहजी राजे की बड़ी-बड़ी हवेलिया पुणे में थी। शाहजी राजे ने पुणे और उसके आसपास का परिसर तेजी से अपने आधिपत्य में लेकर इस क्षेत्र को स्वतंत्र कर लिया। लेकिन शाहजी राजे का ये विद्रोह अधिक समय तक टिक न सका। आदिलशाह ने शाहजी राजे की बड़ी हवेलियाँ जलाकर राख कर दी और उनके अनेक लोगों का वध कर पुणे को वीरान कर दिया। शाहजी राजे का स्वराज के निर्माण हेतु किया गया प्रथम प्रयास असफल रहा। जब लखुजी जाधवराव की हत्या हुई थी, तब गर्भवती जीजाबाई, शाहजी राजे के साथ थी। इस अनिश्चितता के काल में जीजाबाई को इस अवस्था सुरक्षित रखना शाहजी राजे के सामने बड़ी चुनौती थी। शाहजी राजे ने अनुकूलता देख कर जीजामाता को शिवनेरी के किले में रखा। यहाँ जीजाबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया शिवाजी।

## पुणे जागीर का पुनर्निर्माण

जब शाहाजी दक्षिण में व्यस्त थे, तब जिजाबाई ने पुणे क्षेत्र की जागीर का प्रबंधन संभाला। उन्होंने पुणे में लाल महल के निर्माण का मार्गदर्शन किया। इसी लाल महल में शिवाजी का बाल्यकाल बीता और स्वराज्य की प्रारंभिक योजनाएँ बनीं। उनके प्रशासनिक कौशल के कारण युद्धों से उजड़े क्षेत्र में पुन: कृषि, ग्राम व्यवस्था और राजस्व प्रणाली को सुदृढ़ किया गया।

## शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व निर्माण में भूमिका

इस माँ के दो पुत्र थे,एक को दुश्मन ने धोखे से मार दिया था और अब एक ही बेटा अब उसके पास था। जिस माँ ने अपने परिजनों का अलगाव सहन किया हो, अपने पिता, भाइयों और पुत्र की हत्या होते हुए देखी हो, वो माँ अपने बेटे की सुरक्षा के लिए कितनी चिंतित होगी इसकी कल्पना की जा सकती है। लेकिन उस माँ ने अपने एकमात्र बेटे को भी देश के लिए, धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए की रक्षा के लिए तैयार करने का प्रण लिया। इतिहास में जिजाबाई का सबसे बड़ा योगदान छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र निर्माण में माना जाता है। उन्होंने बालक शिवाजी को बचपन से संस्कारित करने के लिए रामायण और महाभारत की कथाएँ सुनाईं। धर्म, न्याय और प्रजा-कल्याण के आदर्श सिखाए। विदेशी और अत्याचारी शासन के प्रति प्रतिरोध की भावना जगाई। स्त्रियों के सम्मान और धार्मिक सहिष्णुता का संस्कार दिया और स्वराज्य के स्वप्न से प्रेरित किया। यह मान्यता है कि शिवाजी के भीतर का स्वराज्य पहले जीजाऊ के मन में जन्मा था।

## हिंदवी स्वराज्य की प्रेरणा

इतिहासकारों के अनुसार हिंदवी स्वराज्य की अवधारणा के पीछे जिजाबाई की प्रेरणा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने शिवाजीराजे को केवल सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि प्रजा की रक्षा,धर्म और संस्कृति के संरक्षण, न्यायपूर्ण शासन, तथा स्वाभिमानी राज्य निर्माण के लिए प्रेरित किया। इसलिए कई इतिहासकार उन्हें 'हिंदवी स्वराज्य की आध्यात्मिक जननी' भी कहते हैं। हर माँ को अपनी संतान की चिंता होना स्वाभाविक है लेकिन उस चिंता के चलते भी देश को पहले रखने का काम जब कोई पन्नाधाय और जीजा माता जैसी माता करती है तब उस देश का इतिहास गढ़ता है। राजमाता जिजाबाई भारतीय इतिहास की उन महान महिलाओं में से हैं जिन्होंने केवल एक पुत्र का पालन-पोषण नहीं किया, बल्कि एक युगपुरुष का निर्माण किया। मराठा इतिहास में उनका स्थान केवल शिवाजी महाराज की माता के रूप में नहीं, बल्कि हिंदवी स्वराज्य की प्रथम प्रेरक, राष्ट्र चेतना की संवाहिका तथा आदर्श प्रशासिका के रूप में है। उन्होने शिवाजी राजे को धर्मपालन, नैतिक शासन, न्याय, और लोककल्याण के भाव को केंद्र में रख कर योजना और नीतियाँ बनाने का शिक्षण और संस्कार दिये।

## महाराज का राज्याभिषेक और अंतिम समय

6 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। यह वह क्षण था जिसका स्वप्न जिजाबाई ने दशकों तक देखा था। राज्याभिषेक के कुछ ही दिनों बाद 17 जून 1674 को उनका निधन हो गया। ऐसा माना जाता है कि स्वराज्य को विधिवत स्थापित होते देखने के बाद उनका जीवन-ध्येय पूर्ण हो चुका था। जिजाबाई का महत्व तीन स्तरों पर समझा जा सकता है 1. राष्ट्रनिर्माता माता- उन्होंने एक ऐसे नेतृत्व का निर्माण किया जिसने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। 2. कुशल मार्गदर्शक- वे केवल माता नहीं थीं स्वराज्य आंदोलन की वैचारिक प्रेरक भी थीं। 3. आदर्श प्रशासिका- पुणे जागीर के संचालन में उनकी प्रशासनिक दक्षता स्पष्ट दिखाई देती है। राजमाता जिजाबाई का जीवन भारतीय इतिहास में मातृत्व, राष्ट्र चेतना, नेतृत्व और सांस्कृतिक आत्मसम्मान का अद्वितीय उदाहरण है। यदि शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य के निर्माता थे, तो जिजाबाई उस स्वराज्य की प्रथम प्रेरणा, वैचारिक आधारशिला और नैतिक शक्ति थीं। मराठा इतिहास में उनका स्थान केवल 'शिवाजी की माता' तक सीमित नहीं है वे स्वयं एक युगनिर्माता व्यक्तित्व हैं।

## जीजामाता के सबक

जो माता अपने बच्चों को हमेशा एक सुरक्षा की खोल में रखती है, उसे परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार नहीं करती उस माँ के बच्चे अपने जीवन में किसी मुकाम को हासिल नहीं कर पाते, जरा से संकट में या थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आने के बाद वे विचलित हो जाते हैं और गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। माँ को यह चाहिए होता है कि वह अपने बच्चों के करियर की चिंता जरूर करें लेकिन उसके साथ उसे अच्छे संस्कार देकर अपने जीवन में किसी बड़े उद्देश्य के लिए जीना सिखाए, बड़ा लक्ष्य उसके सामने रखें और रास्ता हमेशा नैतिकता का हो ये बेहद जरूरी होता है। हर बच्चे के भीतर एक उज्जवल संभावना का बीज छिपा होता है। माँ की यह भूमिका होती है कि वो उस बीज को पहचाने और फिर अपने बच्चों को ऐसा वातावरण दे जिससे वह अच्छी तरह अंकुरित हो सके, पुष्पित पल्लवित हो कर एक वट वृक्ष जैसा विशाल आकर लेकर अपने घर-परिवार के साथ समाज, देश और दुनिया के लिए अच्छा काम कर सके।

गांधी निलय

विवेक कुमार साव

लेखक एच.के.बी.के. डिग्री कॉलेज, कर्नाटक में सहायक आचार्य हैं।

# स्मृति संजोने वाला भवन या अभिजात वर्ग का गेस्ट हाउस?

वर्ष 1936 में महात्मा गांधी की कर्नाटक यात्रा के दौरान नंदी हिल्स की शांत, शीतल वायु और प्राकृतिक सौंदर्य ने उन्हें भी गहराई से आकर्षित किया। 10 मई 1936 को वे नंदी हिल पहुँचे (सम्पूर्ण गांधी वांग्मय, खण्ड-62)। अपने चिकित्सक डॉ. जीराज मेहता की सलाह पर उन्होंने अस्थमा और उच्च रक्तचाप से राहत पाने के उद्देश्य से इसी भवन में लगभग पंद्रह दिन का विश्राम किया। इसके पश्चात् वे लगभग दो सप्ताह बेंगलुरु शहर में रहें।

इस अल्पकालिक किंतु महत्त्वपूर्ण प्रवास के सम्मान में उक्त भवन को 'गांधी निलय' नाम दिया गया। यह छोटा सा भवन आज भी गांधीजी की स्मृतियों को संजोए हुए है। 10 मई 1936 को नंदी हिल पहुँचने के अगले दिन, 11 मई को महात्मा गांधी ने अमृत कौर को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने बताया कि वे पहाड़ी की तलहटी से पैदल ही ऊपर चढ़कर गए थे। इस यात्रा में उन्हें डेढ़ घंटे का समय लगा और उन्होंने पाँच मील से अधिक दूरी तय की। गांधी जी ने अत्यंत धीमी गति से चहलकदमी की थी, जिसके कारण उन्हें कोई थकान महसूस नहीं हुई। उसी पत्र में उन्होंने आगे लिखा कि नंदी हिल स्वच्छता का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है, यद्यपि यह स्वच्छता ऊपर से थोपी गई थी।

'वहाँ का प्राकृतिक वातावरण अत्यंत मनोरम था और चारों ओर स्वर्गीय शांति छाई हुई थी। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि वहाँ मोटर-कारों, अन्य किसी प्रकार की गाड़ियों अथवा रिक्शों का पूर्णतः अभाव था। वे लिखते हैं - मैं नहीं समझता कि नंदी हिल से ज्यादा एकांत, स्वच्छ और शांत कोई और पहाड़ी है। सरदार तो यहाँ की शांति को देखकर खुशी में पागल है।' (सम्पूर्ण गांधी वांग्मय, खंड-62) यही कारण भी है कि इस हिल पर बापू रोज दो घंटे घूमते थे। मणिलाल और सुशीला के पत्रों से यह स्पष्ट होता है कि नंदी हिल पर प्रतिदिन रामायण-पाठ का आयोजन किया जाता था, जिसमें पर्याप्त संख्या में लोग शामिल होते थे। साथ ही, सुबह और शाम की सामूहिक प्रार्थनाएँ नियमित रूप से होती ही थीं। गांधी जी के लिए यह स्थल अत्यंत उपयुक्त था, जहाँ उन्हें पूर्ण शांति और एकांत का लाभ मिलता था। बापू के अतिरिक्त वहाँ सरदार वल्लभभाई पटेल, मणि, कुसुम गांधी, तारा मशरूवाला, नवीन, कांति, कनु, बा, कुमारप्पा, शांता तथा काकासाहब कालेलकर सहित अन्य अनेक सहयोगी भी निवास कर रहे थे।

गांधी जी ने 1 जून 1936 को अमृत कौर जी को लिखे पत्र में नंदी हिल की चर्चा करते हुए कहा है कि इसकी स्फूर्तिदायक हवा और नीरव शांति का अनुभव करने के बाद उन्हें कोई अन्य जगह रुचिकर नहीं लगती। उनके लिए नंदी हिल का जो आकर्षण है, वह किसी अन्य पर्वतीय स्थल में नहीं मिलता। वे लिखते भी हैं - 'मैंने एक लंबी आह के साथ नंदी छोड़ा।' (सम्पूर्ण गांधी वांग्मय, खंड-63) हाल ही में इस गांधी भवन का जीर्णोद्धार किया गया है और इसे विशिष्ट अतिथियों के लिए अतिथिगृह के रूप में उपयोग किया जाता है। परंतु वर्तमान में इस स्थान पर अब एक बोर्ड लगा हुआ है -"PUBLIC ENTRY RESTRICTED" जबकि नंदी हिल पर टीपू सुल्तान का विश्राम भवन, वीरांजनेय मंदिर, टीपू ड्रॉप और पलार नदी का उद्गम स्थल सभी आम जनता के लिए खुला है; जहाँ प्रतिदिन हजारों युवा इतिहास को छूने आते हैं, वहीं गांधी निलय आज भी आम नागरिकों से दूर, प्रतिबंधित बना हुआ है। एक युवा की दृष्टि में यह केवल एक भवन नहीं, बल्कि एक महानायक के चिंतन और विश्राम का साक्षी है। नंदी हिल्स की पहाड़ियों पर घूमते हुए युवा पीढ़ी को यह अवसर अवश्य मिलना चाहिए कि वे बापू की इस स्मृति स्थली को देखें, समझें और प्रेरणा लें। मैं इस जगह के इतिहास से पहले से परिचित था, इसलिए सीधे गेस्ट हाउस के अंदर चला गया। जिन्हें इसका पता नहीं होता, वे बाहर लगे बोर्ड पर लिखी सूचना पढ़कर ही लौट जाते होंगे।

अंदर जाते ही बापू की मूर्ति दिखाई दी। उसके नीचे कन्नड़ और अंग्रेजी में लिखा था, जो युवा देख नहीं पाते - 'सन् 1927 और 1936 में महात्मा गांधी जी बैंगलोर यात्रा के दौरान इसी भवन में ठहरे थे। अपने चिकित्सक डॉ. जीराज मेहता की सलाह पर गांधीजी ने अस्थमा और उच्च रक्तचाप से उबरने के लिए यहाँ 45 दिनों तक विश्राम किया था।

गांधी जी के इस छोटे से भवन में ठहरने के सम्मान में इसका नाम गांधी निलय रखा गया है। इस भवन का हाल ही में जीर्णोद्धार किया गया है और इसे विशेष अतिथियों के लिए अतिथिगृह के रूप में उपयोग किया जा रहा है।' यहाँ एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उभरता है कि क्या महात्मा गांधी की स्मृतियों से जुड़ा यह स्थल केवल कुछ चुनिंदा अतिथियों और विशिष्ट व्यक्तियों तक ही सीमित रह जाए? या फिर इसे उन युवाओं, विद्यार्थियों, शोधार्थियों और आम नागरिकों के लिए भी खोल दिया जाए, जो गांधी के जीवन और उनके विचारों को करीब से महसूस करना चाहते हैं? नंदी हिल पर स्थित गांधी निलय केवल भवन भर नहीं, बल्कि इतिहास का एक साक्ष्य है। यदि इसे संरक्षित रखने के साथ-साथ आम लोगों के लिए भी आंशिक रूप से खोला जाए, तो यह आने वाली पीढ़ियों को गांधीजी के जीवन और उनके विचारों से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है।

# बच्चों के हाथों में मोबाइल: माता-पिता दोषी

शोध

संदीप कुलश्रेष्ठ

पीजीआई चंडीगढ़ की पीडियाट्रिक्स और सोशल पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट की प्रोफेसर नवनीत भारती और उनकी टीम द्वारा की गई रिसर्च के अनुसार करीब 68 प्रतिशत बच्चें 18 महीने की उम्र से पहले ही स्क्रीन के सम्पर्क में आ जाते हैं। यह स्टडी प्रतिष्ठित इंडियन जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स में प्रकाशित हुई है। इस रिसर्च में 18-24 महीने के छोटे बच्चों को शामिल किया गया था।

उक्त शोध में यह सामने आया है, कि स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों की सीखने और दूसरों से बातचीत करने की क्षमता को धीमा कर रहे हैं। इसके साथ ही मोबाइल देखते हुए खाना खाने की गलत आदत के साथ भाषा और ध्यान लगाने की क्षमता पर भी गहरा असर डाल रही है। जिससे बच्चे अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं।

शोध में बचपन खतरे में बताते हुए डॉक्टरों ने सलाह दी है कि बच्चों के विकास के लिए मैदानी खेल जरूरी है। छोटे बच्चें निष्क्रिय होकर स्क्रीन देखने की बजाय अपने माता-पिता और आसपास के वातावरण से सीधे संवाद करके सबसे बेहतर सीखते हैं। शोध में यह भी बताया गया कि बच्चों को स्क्रीन की नहीं, बल्कि माता-पिता के साथ की, कहानियों की और खुले मैदानों में खेलने की जरूरत है।

शोध से भयावह तस्वीर दिखाई देती है। माता-पिता के अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण वे अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। वे बच्चों को व्यस्त रखने के लिए उनके हाथों में मोबाइल पकड़ा देते हैं। बच्चा उसमें व्यस्त हो जाता है और वे निष्क्रिय होते चले जाते हैं। माता-पिता और अभिभावक यदि ठान लें कि वे अपने छोटे बच्चों को समय देंगे, उन्हें कहानियाँ सुनाएंगे और मैदानी खेल में उन्हें व्यस्त रखेंगे, तो निश्चित ही बच्चा मोबाइल का आदी नहीं हो पाएगा। माता-पिता और अभिभावक ही पूरी तरह से दोषी है, बच्चों को मोबाइल की लत लगाने में। इसमें बच्चा दोषी नहीं है। यहाँ सुधरने की जरूरत बच्चों को नहीं, बल्कि बच्चे के माता-पिता और अभिभावकों की है।

शोध में डेढ़ साल तक के 68 प्रतिशत बच्चों के हाथों में मोबाइल होना पाया गया। किन्तु अभी भी 32 प्रतिशत बच्चें ऐसे हैं, जो मोबाइल से बचे हुए हैं। इनके माता-पिता ने शुरू से बच्चों को मोबाइल की लत लगने ही नहीं दी। ऐसे बच्चों के माता-पिता आदर्श हैं। 68 प्रतिशत बच्चों के माता-पिता को इन 32 प्रतिशत वाले बच्चों के माता-पिता से सीखना चाहिए। बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए जरूरी है, उन्हें मोबाइल से बचाकर रखना। और इसी से बच्चों का बचपन बच पाएगा, अन्यथा उनका बचपन खतरे में हैं।

यादों में बचपन

तनुजा चौबे

लेखक साहित्यकार हैं।

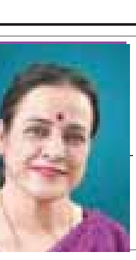

# कॉलोनियों में थोड़ा मोहल्ला बचा रहना चाहिए

**आज की यह दौड़ती-भागती ज़िंदगी, जिसे सरल बनाने के लिए तरह-तरह के गैजेट्स, लग्ज़री आइटम और आधुनिक सुविधाएँ जुटा ली गई हैं, उसमें अब मोहल्ले नहीं, बल्कि लग्ज़री टाउनशिप बसती हैं। आधुनिक जीवनशैली के साथ इंसानों के असली चेहरों पर ही नहीं, भावनाओं पर भी मुखौटे चढ़ गए हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या आज के परिवेश की ये बातें आने वाले कल में खूबसूरत यादों की धरोहर बन पाएँगी?**

खुशगवार मौसम ही हमें यादों की गलियों में नहीं ले जाता, बल्कि जीवन की अनेक खट्टी-मीठी स्मृतियाँ भी हमें उन पुराने मोहल्लों तक पहुँचा देती हैं, जहाँ हमारा बचपन साँस लेता था। क्या कभी हमने सचमुच 'मोहल्ले' की याद के बारे में सोचा है?

आज की यह दौड़ती-भागती ज़िंदगी, जिसे सरल बनाने के लिए तरह-तरह के गैजेट्स, लग्ज़री आइटम और आधुनिक सुविधाएँ जुटा ली गई हैं, उसमें अब मोहल्ले नहीं, बल्कि लग्ज़री टाउनशिप बसती हैं। आधुनिक जीवनशैली के साथ इंसानों के असली चेहरों पर ही नहीं, भावनाओं पर भी मुखौटे चढ़ गए हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या आज के परिवेश की ये बातें आने वाले कल में खूबसूरत यादों की धरोहर बन पाएँगी?

आज यादें भी गैजेट्स में सुरक्षित होती हैं, जो एक क्लिक में हमेशा के लिए मिट सकती हैं। हाई प्रोफाइल ज़िंदगी के चेहरों पर ही नहीं, दिलों पर भी एक आवरण चढ़ गया है, जिसके कारण भावनाएँ अब दिल तक पहुँच ही नहीं पातीं।

वह समय कुछ और ही था। प्रचंड गर्मी में आँगन में पानी छिड़ककर खटिया डाल दी जाती थी और पूरे मोहल्ले के बच्चे खुले आसमान के नीचे सोते थे। मन में किसी काली परछाई का डर नहीं होता था, न ही किसी मासूम बचपन के रौंदे जाने का भय। उस निडर बचपन की साँसों में जो उन्मुक्तता थी, वही असली जीवन था।

सुबह जब सूरज की पहली किरण खटिया की निवाड़ को छूती थी, तब हल्की ठंडक का एहसास होता था। पक्षियों की चहचहाहट सुनकर आँख खुलती थी, न कि मोबाइल के अलार्म से। आज की तरह भागते हुए उठकर रोबोट की तरह दिनचर्या में नहीं जुटना पड़ता था।

आज बच्चों को भी मशीनी जीवन दिया जा रहा है। स्कूल बस के समय के पीछे भागती सुबहें, जल्दी-जल्दी तैयार होते बच्चे- सब कुछ एक दौड़ बन गया है। याद आती है वह सुबह, जब ब्रेड-जैम, ग्रेन्यूला या ऑर्गेनिक फूड्स की जगह बच्चे चाय में ठंडी रोटी का रोल बनाकर बड़े स्वाद से खाते थे। माँ रात में ही बच्चों के लिए रोटियाँ बनाकर रख देती थी। क्या वह ममता ब्रेड-जैम देने वाली ममता से कम थी? शायद नहीं, बल्कि कहीं अधिक थी। वह माँ बच्चों की सुबह की चिंता रात में ही कर लेती थी।

गर्मी की दोपहरों में ए.सी. या कूलर में आराम करने के बजाय बच्चे नए-नए खेल खेलते थे। हर घर के आँगन में नीम का पेड़ होता था, जिसकी घनी छाँव के नीचे पीली-पीली निंबोलियाँ गिरती रहती थीं। बच्चे उन्हें इकट्ठा करते और पॉलिश की डिब्बियों या मिट्टी के दियों से तराजू बनाकर आम की दुकान-दुकान खेलते।

माचिस की डिब्बियों में धागा बाँधकर बच्चे दूर बैठकर आपस में बातें करते थे। उस धागे की कंपन में भी दोस्ती का संचार होता था। कार्डबोर्ड के बने तिकोने कोन में काँच लगाकर और उसमें टूटी चूड़ियों के टुकड़े डालकर जब उसे घुमाकर देखते, तो रंग-बिरंगी आकृतियाँ बनतीं और बच्चे खुशी से खिल उठते।

कभी-कभी शाम को डब्बे वाला सिनेमा भी आता था। वह ऊपर लगी चकरी घुमाकर भीतर लगे पोस्टर दिखाता था और हमें लगता था जैसे सचमुच फिल्म चल रही हो। उन छोटी-छोटी खुशियों में कितना बड़ा आनंद छिपा था। आज के बच्चे घंटों मोबाइल, लैपटॉप और टीवी के सामने बैठे रहते हैं। तरह-तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म मनोरंजन के असंख्य व्यंजन परोसते हैं, लेकिन वह सादगी भरा आनंद कहीं खो गया है।

हमारे समय में मौसमों के अनुसार खेल बदल जाते थे। गर्मी के खेल अलग, बारिश के खेल अलग। आज कॉलोनियों में रहने वाले बच्चे केवल निर्धारित बगीचों में खेलते हैं और माताएँ कहती हैं - 'डोंट रन ऑन द रोड।' जिन बच्चों को रोड और ट्रैक का अंतर भी ठीक से नहीं मालूम, उन्हें जागरूक बनने की सीख दी जाती है।

वहीं हमारा बचपन पेड़ों की डालियों पर चढ़ते, एक-दूसरे के पीछे दौड़ते और मिट्टी में खेलते बीता। यही हमारी कसरत थी और यही जीवन का उत्साह।

गर्मी की छुट्टियों में खटिया पर सेवई मशीन लगाकर सेवइयाँ बनाई जाती थीं। बारी-बारी से बच्चों को मशीन चलाने का काम दिया जाता था। वह काम खेल भी था और व्यायाम भी। घरों में हाथ वाली चक्की होती थी, जिसमें अनाज और सत्तू पीसा जाता था। खेल-खेल में बच्चे भी उसे चलाते थे। लड़कियाँ पाँचें खेलती थीं। आज ये सारे खेल और गतिविधियाँ लगभग विलुप्त हो चुके हैं।

आज बच्चों को स्विमिंग क्लास, बैडमिंटन क्लास और क्रिकेट अकादमी भेजा जाता है। सड़क पर खेलने वाले बच्चे अच्छे नहीं माने जाते। लेकिन जब बच्चे मिट्टी में ही नहीं खेलेंगे, तो मिट्टी से जुड़ाव और जीवन की मजबूती कैसे आएगी?

आज के बच्चे चकरी की तरह एक क्लास से दूसरी क्लास में घूमते रहते हैं और भीतर ही भीतर अपने अकेलेपन से लड़ते रहते हैं। माता-पिता के पास समय नहीं है, इसलिए धीरे-धीरे बच्चों की संवेदनाएँ भी कम होती जा रही हैं।

आखिर वही पीढ़ी तैयार होगी, जिसने केवल हाई प्रोफाइल जीवन देखा है। दिल के चारों ओर दीवारें खड़ी करके जीना सीखा है। बारिश में लग्ज़री कार से घर से निकलने वाले लोग बारिश का असली आनंद कैसे समझ पाएँगे? यदि वे भीग जाएँ, तो उन्हें मौसमी एलर्जी हो जाती है। वहीं मोहल्ले के बच्चे बारिश का इंतज़ार करते थे। कीचड़ से गुजरना, पानी भरे गड्ढों में कागज़ की कश्तियाँ चलाना, गीली मिट्टी में सरिया गाड़कर खेलना, गिल्ली-डंडा खेलते हुए दूर निकल जाना- यही उनकी दुनिया थी। न उन्हें जल्दी सर्दी होती थी, न बुखार। घर लौटकर हैंडपंप से पानी निकालकर नहा लेना ही उनकी दिनचर्या थी।

यह कहना उचित नहीं होगा कि आज की परवरिश गलत है, लेकिन इतना अवश्य है कि अब कॉलोनियों में रहने वाले परिवार आपस में बातचीत तक नहीं करते। बच्चों का परिचय तो दूर, बड़ों के बीच भी अपनापन कम हो गया है।

इंडोर गैजेट गेम्स का प्रचलन बढ़ गया है और आउटडोर गतिविधियाँ कम हो गई हैं। शायद कॉलोनियों में थोड़ा 'मोहल्ला' बचा रहना चाहिए, ताकि वही संवेदनाएँ फिर विकसित हो सकें, जो धीरे-धीरे विलुप्त होती जा रही हैं।

## सोलहवीं मध्यप्रदेश विधानसभा के एकादश सत्र की अधिसूचना जारी

**भोपाल।** मध्यप्रदेश की सोलहवीं विधानसभा का एकादश सत्र सोमवार, दिनांक 20 जुलाई, 2026 से आरंभ होकर शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026 तक चलेगा। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमोदित तदाशय की अधिसूचना आज विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी कर दी गई है। इस 5 दिवसीय सत्र में महत्वपूर्ण शासकीय कार्य संपादित किए जायेंगे। इस हेतु विधानसभा सचिवालय में अशासकीय विधेयकों की सूचनाएं 24 जून, 2026 तथा अशासकीय संकल्पों की सूचनाएं 9 जुलाई, 2026 तक प्राप्त की जावेंगी। जबकि स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, नियम 267 – क के अधीन सूचनाएं विधानसभा में 14 जुलाई, 2026 से कार्यालय में पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 तक प्राप्त की जावेंगी। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश की सोलहवीं विधानसभा का यह एकादश सत्र होगा।

## सेमरी हरचंद में सीड बाल का निर्माण

**सोहागपुर।** नवांकुर अभियान के अंतर्गत सेमरीहरचंद विद्यालय में 350 से अधिक सीड बॉल का निर्माण किया गया। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशन में पर्यावरण संरक्षण एवं हरित क्षेत्र के विस्तार हेतु संचालित 'नवांकुर अभियान' के अंतर्गत विकासखंड सोहागपुर के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सेमरीहरचंद में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सोहागपुर सुश्री प्रियंका भलावी की उपस्थिति में सीड बॉल निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के सामूहिक प्रयास से 350 से अधिक सीड बॉल तैयार किए गए। कार्यक्रम में सहायक संचालक बीईओ राकेश कुमार उइके, विकासखंड स्त्रोत समन्वयक राकेश रघुवंशी, विद्यालय के प्राचार्य संतोष ठाकुर, समस्त शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यशाला के दौरान विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण के महत्व, जैव विविधता संवर्धन तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इसके साथ ही सीड बॉल निर्माण की प्रक्रिया एवं इसके पर्यावरणीय लाभों के बारे में भी अवगत कराया गया। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी सुश्री प्रियंका भलावी ने विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने तथा हरित गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता निभाने के लिए प्रेरित किया। आपने कहा कि नवांकुर अभियान केवल वृक्षारोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता एवं जन-सहभागिता का व्यापक अभियान है।

# 18 जून को बैतूल आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

● आयोजन को लेकर पत्रकारवार्ता आयोजित ● पासधारकों को ही मिलेगा प्रवेश, रहेगी विशेष सुरक्षा व्यवस्था

**बैतूल।** जिला मुख्यालय पर 18 जून को होने वाले आध्यात्मिक महासम्मेलन और जनजातीय जागरण कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। इस ऐतिहासिक आयोजन में देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। कार्यक्रम का आयोजन ब्रह्माकुमारी संस्था द्वारा किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोगों के साथ विभिन्न ब्रह्माकुमारी क्षेत्रों के गणमान्य नागरिक भी शामिल होंगे। संस्था से जुड़े डॉ. नयनल भाई (ओडिशा) ने पत्रकार वार्ता में बताया कि कार्यक्रम स्थल लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम को चारों ओर से सजाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क एवं तैयार है। स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, आदिवासी स्वागत गीतों और पारंपरिक नृत्य प्रस्तुतियों का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अपने आध्यात्मिक अनुभवों को उपस्थित जनसमुदाय के साथ साझा करेंगी। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम में प्रवेश केवल वैध पास के माध्यम से ही दिया जायेगा। आधार नंबर और मोबाइल नंबर के आधार पर पंजीकरण कर अधिकृत पास जारी किए गए हैं। तीन सौ पास गणमान्य के लिए जारी किए गए हैं। इसके अलावा दो हजार पास प्रशासन को दिए गए हैं, जिनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों से लोग बसों से बैतूल आएंगे। 2800 पास ब्रम्ह कुमारी संस्था से जुड़े लोगों को वितरित किए गए हैं। लगभग पांच हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। सभी पासों का वितरण लगभग पूरा हो चुका है। विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग बैठक व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि गेट नंबर-1 से राष्ट्रपति का प्रवेश होगा। गेट नंबर-2 से वीआईपी अतिथियों का प्रवेश रहेगा। गेट नंबर-3 एवं 4 से आम नागरिकों को प्रवेश दिया जाएगा।

**देश भर से पहुंचे ब्रह्माकुमारी परिवार के सदस्य** – माउंट आबू से पहुंचीं ब्रह्माकुमारी डॉ. लीना बहन ने बताया कि बैतूल में आयोजित यह कार्यक्रम जनजातीय समाज के

सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन को साकार करने में बैतूल सेवा केंद्र की प्रभारी मंजू दीदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके प्रयासों से ही राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का संकल्प सफल हो सका। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में माउंट आबू सहित देशभर से ब्रह्माकुमारी परिवार के सदस्य पहुंच चुके हैं और बैतूल अब एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रहा है।

**कई बड़े नेता और अधिकारी रहेंगे मौजूद** – आयोजन में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय एवं प्रदेश स्तर के कई जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके, प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल सहित कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहेंगी। मुख्य कार्यक्रम सुबह 11.20 बजे शुरू होकर लगभग 12.10 बजे तक चलेगा। आयोजकों ने नागरिकों से समय से पहले पहुंचने की अपील की है। आंमजन को सुबह 9 बजे तक अपनी निर्धारित सीटों पर पहुंचने का आग्रह किया गया है। सुबह 9 बजे से ही सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रस्तुतियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा।

## वीवीआईपी मार्ग रहेगा सैनिटाइज, भारी वाहनों के प्रवेश पर रहेगा प्रतिबंध

● परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए विशेष वैकल्पिक मार्ग निर्धारित ● विभिन्न स्थानों पर बनाई गई पार्किंग व्यवस्था

**बैतूल।** राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित बैतूल भ्रमण कार्यक्रम के मद्देनजर जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा व्यापक सुरक्षा, यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। थाना यातायात बैतूल द्वारा जारी सूचना के अनुसार कार्यक्रम के दौरान यातायात को सुचारु बनाए रखने, आमजन की सुविधा तथा सुरक्षा मानकों के पालन के लिए विशेष मार्ग, पार्किंग स्थल एवं वैकल्पिक रूट निर्धारित किए गए हैं। गंज रेलवे स्टेशन क्षेत्र से आने वाले वाहन मैकेनिक चौक, गुरुद्वारा रोड एवं रैन बसेरा चौक मार्ग से कार्यक्रम स्थल पहुंच सकेंगे। मुलताई क्षेत्र से आने वाले वाहनों को परतापुर, बैतूल बाजार, एलबी लॉन, बडोरा चौक एवं गेंदा चौक मार्ग का उपयोग करना होगा। इंदौर हाईवे की ओर से आने वाले वाहन तितली चौराहा, करबला मार्ग, डॉन बॉस्को स्कूल एवं राम बोले चौक होते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे। वहीं आमला रोड से आने वाले वाहनों के लिए हमलापुर चौक, वन विद्यालय, तिवारी पेट्रोल पंप, काली चट्टान रोड, ग्रीन सिटी, भग्गूडाना, आबकारी तिराहा, रेलवे स्टेशन, मैकेनिक चौक, गुरुद्वारा रोड एवं रैन बसेरा चौक होकर कार्यक्रम स्थल पहुंचने की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए 18 जून को प्रातः 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक बैतूल नगर सीमा में भारी एवं मध्यम वाहनों, ट्रैक्टर एवं ट्रॉलियों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग ने आमजन से अपील की है कि निर्धारित यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था का पालन करें, यात्रा के दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें तथा सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन में प्रशासन का सहयोग करें, जिससे कार्यक्रम के दौरान व्यवस्था सुचारु एवं सुरक्षित बनी रहे।

**निर्धारित किया गया विशेष मार्ग** – राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू का कार्केट हेलीपैड मिलानपुर से भारत भारती, सोनाघाटी फॉरेस्ट बैरियर, चक्कर रोड, थाना कोतवाली चौक, गणेश मंदिर, कॉलेज चौक, पुलिस कंट्रोल रूम चौक, पुलिस पेट्रोल पंप होते हुए लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेगा। थाना यातायात द्वारा जारी सूचना के अनुसार सुरक्षा कारणों से 18 जून को प्रातः 9 बजे से 10.15 बजे तक राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू के कार्केट मार्ग को पूर्णतः खाली एवं सैनिटाइज रखा जाएगा। साथ ही एंटी-सबोटाज जांच पूर्ण होने के बाद कार्केट मार्ग पर किसी भी प्रकार के वाहन संचालन की अनुमति नहीं होगी।

**वीआईपी, प्रशासनिक एवं आमजन के लिए अलग पार्किंग** – कार्यक्रम में शामिल होने वाले अतिथियों एवं आमजन के वाहनों के लिए पृथक-पृथक पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं। दक्ष केंद्र शिवाजी चौक में वीवीआईपी एवं वीआईपी पार्किंग, पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में पुलिस प्रशासनिक पार्किंग, पुलिस परेड ग्राउंड अंबेडकर चौक में दोपहिया वाहन पार्किंग तथा रैन बसेरा चौक के समीप चारपहिया वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। इसके अतिरिक्त गुरुद्वारा रोड स्थित आदिवासी छात्रावास के सामने पुलिस परेड ग्राउंड गेट तथा उत्कृष्ट विद्यालय खेल मैदान (हॉकी स्टेडियम के समीप) में भी पार्किंग स्थल बनाए गए हैं।

**महाविद्यालयीन परीक्षार्थियों के लिए विशेष यातायात व्यवस्था** – महाविद्यालयीन परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए विद्यार्थियों के लिए विशेष यातायात व्यवस्था भी की गई है। शाहपुर एवं सारणी क्षेत्र से आने वाले परीक्षार्थियों के लिए शाहपुर, पाथाखेड़ा जोड़, घोड़ाडोंगरी, रानीपुर, चिखलार, पहाड़ी अस्पताल मार्ग, खासी खदान, अवस्थी गोदाम, अखवाड़ा चौक, लिंक रोड एवं कारगिल चौक मार्ग निर्धारित किया गया है।

## शिव पार्वती मंदिर के निकट पेट्रोल पंप पर कांग्रेस का प्रदर्शन, की नारेबाजी लोगों ने मिलाए स्वर से स्वर

**सोहागपुर।** कांग्रेस नेता पुष्पराजसिंह पटेल पूरी विधानसभा में कोई भी मुद्दे को तत्काल ही पकड़कर सहानभूति लेने का मौका नहीं छोड़ते है। यह पिछले चुनाव में अजेय विधायक विजयपालसिंह से पराजित होने के बाद से निरंतर जारी रखें हुए हैं। इसका कितना लाभ पुष्पराज सिंह पटेल को मिलेगा। यह तो समय ही बताएगा। हालांकि आगामी चुनाव में कांग्रेस किसको प्रत्याशी बनाती है यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस ने अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपने के उपरांत कांग्रेस जन पुष्पराज सिंह पटेल के नेतृत्व में नर्मदापुरम पिपरिया राज्य मार्ग शिव पार्वती मंदिर पर स्थित एक पेट्रोल पंप पहुंचे। पुष्पराज सिंह पटेल एक ट्रेक्टर में बैठे चल रहे थे। यहां पहले से ही दो पहिया वाहनों में पेट्रोल एवं डीजल लेने वालों की भारी संख्या थीं। उल्लेखनीय है कि यहां कांग्रेस पदाधिकारियों के दो, तीन पेट्रोल पंप हैं। जिसमें विगत दिनों से न पेट्रोल है न ही डीजल उपलब्ध है। ऐसे एक ही पेट्रोल पंप शिव मंदिर के निकट है। इससे कम से कम दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों के छक्के जाम होने से बच रहें हैं। नहीं तो सोहागपुर में पेट्रोल एवं डीजल के लिए त्राहि-त्राहि मच जाती। यहां कांग्रेस जन के पहुंचने पर पुष्पराज पटेल ने मंहगाई, जीना है तो लड़ना सीखों के अलावा मुर्दाबाद के नारे लगाए। नारेबाजी में उपस्थित जनों ने स्वयं से स्वर मिलता। वहीं कहां कि अबकी बार कांग्रेस सरकार। आदि पर जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पुष्पराज सिंह पटेल, छोटे सरकार गलचा, पूर्व नपाध्यक्ष संतोष मालवीय, ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष सुधीर ठाकुर, पार्षद भास्कर मांझी, इरफान खान, राजा भैया पटेल सहित कई कांग्रेस जन किसान, पंजाब के हार्वेस्टर वाले, एवं पेट्रोल एवं डीजल लेने वाले ग्राहक उपस्थित थे। इधर पता चला है कि सेमरी हरचंद में एक पेट्रोल पंप कई दिनों से बंद है। वहीं सोहागपुर के श्री अग्रवाल ही सोहागपुर की तरह सेमरी हरचंद में पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति कर रहे हैं। इससे आस-पास के ट्रेक्टरों की भारी संख्या पेट्रोल पंप पर डीजल लेने पहुंच रहे हैं। हालांकि अब अमेरिका एवं ईरान में समझौता हो गया है। इससे यह किल्लत जल्दी ही दूर होने की संभावना है।

## जिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से करेगा शिष्टाचार भेंट, कलेक्टर को सौंपा आवेदन

**बैतूल।** 18 जून को देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बैतूल आगमन के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी ने उनसे शिष्टाचार मुलाकात के लिए समय देने का अनुरोध किया है। जिला कांग्रेस कमेटी बैतूल के अध्यक्ष निलय विनोद डागा ने कलेक्टर को आवेदन सौंपकर बताया कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मुलाकात कर जिले के किसानों को खाद, बीज और डीजल की समस्या, राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन का चुनाव आयोग द्वारा फार्म निरस्त किए जाने, बैतूल जिले में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार तथा सडक, स्वास्थ्य और ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता है। आवेदन के अनुसार प्रतिनिधिमंडल में जिला कांग्रेस अध्यक्ष निलय विनोद डागा, पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह उइके, पूर्व विधायक ब्रम्हा भलावी, पूर्व विधायक धरमूसिंह सिरसाम, पूर्व विधायक डॉ. पी.आर. बोडखे, प्रदेश सचिव समीर खान, जिला कांग्रेस प्रवक्ता लवलेश बब्बा राठौर, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष हर्षवर्धन धोटे, संगठन महासचिव ब्रजभूषण पांडे और जिला कांग्रेस कोषाध्यक्ष लोकेश पगारिया शामिल रहेंगे। कांग्रेस ने कलेक्टर से अनुरोध किया है कि उक्त प्रतिनिधिमंडल को राष्टपति से शिष्टाचार मुलाकात के लिए समय उपलब्ध कराया जाए, ताकि जिले से जुड़े महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दे उनके समक्ष रखे जा सकें।

## माँ वाग्देवी की पावन धरा धारा नगरी की टिशा ठाकुर युवा संगम फेज -6 में चयनित, बढ़ाया मान

### झारखंड में धार जिले और मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही प्रतिभाशाली टिशा

**राजेश शर्मा, धार।** माँ वाग्देवी की पावन धरा-राजा भोज की ऐतिहासिक धारा नगरी मानों इस पावन माटी ने एक से बढ़कर एक प्रतिभाओं को जन्मा है। इस माटी में पली बढ़ी कई प्रतिभाएं देश और दुनिया में धार को गौरवान्वित कर रही है। बहुत छोटे से गांव से आने वाली ऐसी ही एक प्रतिभाशाली बिटिया टिशा ठाकुर अपनी प्रतिभा और कुछ कर गुजरने की चाह के चलते धार जिले को झारखंड में गौरवान्वित कर रहीं हैं। 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पहल के तहत चलने वाला यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम युवा संगम फेज -6 में चयनित हो कर टिशा ने धार जिले का मान बढ़ाया हैं। झारखंड में धार जिले और मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही टिशा धार जिले की संस्कृति, सभ्यता एवं अपने विचारों को साझा करेगी। वाग्देवी माँ सरस्वती जी की कृपा से वह अपनी धरा के गौरव को नये आयाम दिलाने के लिए संकल्पित है धार के पीजी कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष में अध्ययनरत टिशा सहित युवा संगम में चयनित अन्य युवाओं को झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार ने रांची स्थित राजभवन में सम्मानित किया। आईआईटी धनबाद में यह आयोजन 10 से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है। टिशा युवा संगम फेज -6 में धार जिले और देश के दिल मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व कर बेहद उत्साहित हैं।

**क्या है युवा संगम...**

देश के अलग-अलग राज्यों के युवाओं को एक-दूसरे की संस्कृति, परंपरा, विकास कार्यों और तकनीक से रूबरू कराना। राष्ट्रीय एकता मजबूत करना। चयनित युवाओं को दूसरे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में 5-7 दिन की शैक्षिक और सांस्कृतिक यात्रा करने का अवसर मिलता है।

- स्थानीय संस्कृति और पर्यटन स्थल
- विकास परियोजनाएं और औद्योगिक इकाइयां
- तकनीकी नवाचार और शैक्षणिक संस्थान को जानने का मौका मिलता है यूथ को।

**कार्यक्रम की मुख्य थीम -(5 पी)**

1. पर्यटन
2. परंपरा
3. प्रगति
4. पारस्परिक संपर्क
5. प्रौद्योगिकी और नवाचार

## सरकार किसानों की वास्तविकता समझे, हमें ट्रेक्टर में 50, टंकी में 150 लीटर डीजल दे, एसडीएम को ज्ञापन सौंपा

**सोहागपुर।** डीज़ल की समस्या को लेकर ब्लाक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में पुराने के सामने कांग्रेस एवं किसानों की भीड़ निर्धारित समय 11बजे के बाद बढ़ती रही। कांग्रेस नेता पुष्पराजसिंह पटेल एक रिंग वाले ट्रेक्टर पर बैठे अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां नारेबाजी के बाद अनुविभागीय अधिकारी प्रियंका भल्लावी को डीजल की समस्या के लिए ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर नवनियुक्त नगर निरीक्षक गिरीश त्रिपाठी भी उपस्थित थे। ज्ञापन का वाचन नगर कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत जायसवाल ने किया। ज्ञापन में कहा गया है कि शासन की डीजल सप्लाई के संबंध में जो आदेश जारी किये गए हैं। इससे किसानो की समस्याये और भी बढ़ गई हैं। इस समय किसान की मूंग की कटाई चल रही है। इसके तुरंत बाद किसान को धान की रोपाई करना है। इस संदर्भ में किसान को अपनी आवश्यकता अनुसार डीजल की आवश्यकता हैं। परन्तु इस समय पेट्रोल पंपों पर शासन के आदेश अनुसार किसान को केन और वैरल में डीजल नहीं दिया जा रहा है। इस कारण किसान को अपने खेत से निकालकर टेक्टर और हर्बेस्टर पेट्रोल पम्पो पर लाने पड़ रहे हैं। इस कारण किसान का कृषि कार्य समय पर नहीं हो पा रहा हैं। वहीं आने जाने के रास्ते में जलने वाले डीजल का खर्च किसान पर अधिक पड़ रहा हैं। अतः माननीय कलेक्टर से निवेदन है।कि किसान को 200 लीटर के वैरल में और 50 लीटर की केन में डीजल दिया जाना सुनिचित करे। अगर तत्काल किसानों की इस मांग को नहीं माना गया तो हमें उग्र आन्दोलन करने को बाध्य होना पड़ेगा। जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस अवसर पर पुष्पराज सिंह पटेल ने एसडीएम प्रियंका भल्लावी को बताया कि हम सब किसान भी है। सरकार का कहना है कि किसानों को डीजल दो सौ लीटर दिया। लेकिन केन बेतवा में न देवें। ट्रेक्टर में 50 लीटर की टंकी है। हमें शेष 150लीटर टंकी या बेरल में दिया जाए। इससे किसानों को राहत मिल सकेगी। आपने एसडीएम को बताया कि यदि किसान दूरदराज से ट्रेक्टर लेकर बार बार आएगा तो आने जाने में ही उसका अधिकांश डीजल व्यर्थ में ख़र्च हो जाएगा। अतः हमारी बात माननीय कलेक्टर एवं सरकार तक पहुंचा दें। आपने आगे कहा कि वर्तमान की परिस्थितियों में यदि किसान अपने अपने ट्रेक्टर बार बार लेकर पेट्रोल तक लेकर आएगा ऐसी स्थिति में रास्ते में जाम की स्थिति बन सकती है। जिससे प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ेगी। इसके साथ ही किसानों की परेशानी कम होने के बदले बढ़ जाएगी। इसी अवसर पर आपने एसडीएम को कहा कि अभी तक ग्राम नवलगांव के किसानों को गेहूं खरीदी का भुगतान नहीं हुआ है। इस अवसर पर कांग्रेस नेता पुष्पराजसिंह पटेल, छोटे सरकार खर्चा, ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष सुधीर ठाकुर, मनीष पटेल, सुरेखाशाह शोभापुर, पूर्व नपाध्यक्ष संतोष मालवीय, वकील मंगलसिंह रघुवंशी, नीरज चौधरी, राजकुमार पटेल, जिला जनपद पंचायत सदस्य दौलतराम पटेल, ऋषभ दीक्षित, सचिन श्रोती, चमन रघुवंशी, इरफान खान, वरिष्ठ पार्षद धर्मदास बेलवंशी, पूर्व पार्षद मोहन कहार, पार्षद भास्कर मांझी राजा भैया पटेल सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं किसान उपस्थित थे।

## सेमरीहरचंद में नवनियुक्त नगर निरीक्षक ने किया पैदल भ्रमण

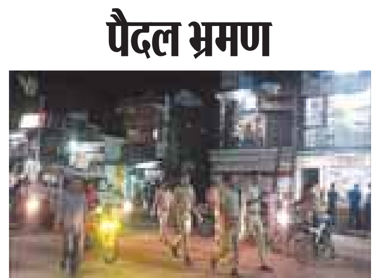

**सोहागपुर।** विगत दो पूर्व पिपरिया से तबादला होकर सोहागपुर नगर निरीक्षक का पदभार ग्रहण किया था। इसके उपरांत ही गिरीश त्रिपाठी ने लंबित मामले में पिपरिया नर्मदापुरम राज्य मार्ग के सतपुडा टाइगर रिजर्व मढ़ई जाने वाले रास्ते पर दो ढाबा के अतिक्रमण को पुलिस एवं राजस्व टीम संयुक्त टीम के साथ जेसीबी मशीन से हटाया गया। एसडीएम सोहागपुर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि कलेक्टर नर्मदापुरम के द्वारा चलाये जा रहे अतिक्रमण की कार्यवाही के परिपालन मे आज अनुविभागीय अधिकारी प्रियंका भलावी के निर्देशन में शासकीय भूमि अंतर्गत ग्राम बम्होरीखुर्द, राजस्व प्रकरण क्रमांक 16/अ-68/2025-26 में पटवारी हल्का क्रमांक 20 ग्राम बम्होरीखुर्द स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 272 एवं 291, कुल रकबा 3.913 एवं 0.709 हेक्टेयर में से लगभग 0.040 हेक्टेयर भूमि पर अमित चौरसिया पिता रमेश चौरसिया वहीं राजस्व प्रकरण क्रमांक 17/अ-68/2025-26 में यह पाया गया कि ग्राम बम्होरीखुर्द की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 272, रकबा 3.913 हेक्टेयर में से लगभग 3300 वर्गफुट भूमि पर महेन्द्रसिंह पिता सुल्तानसिंह, निवासी ग्राम नयाकूकरा के ढाबा से शासकीय भूमि पर अतिक्रमण मुक्त किया गया। इसी क्रम में कानून व्यवस्था को लेकर कल रात सोहागपुर पुलिस थाने के अंतर्गत सेमरी हरचंद पुलिस चौकी प्रभारी के साथ सेमरी हरचंद के मुख्य मार्गों पर पैदल भ्रमण किया।

## भोपाल शहर एवं भोपाल ग्रामीण क्षेत्र के 4 लाख 7 हजार 216 उपभोक्ताओं को

● मई माह में 4 करोड़ 40 लाख की छूट

● स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मिला सोलर ऑवर में 20 प्रतिशत छूट का लाभ

**भोपाल।** मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के अंतर्गत स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनके मासिक विद्युत बिल में टाइम ऑफ डे (ToD) छूट का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में मई 2026 के दौरान भोपाल शहर एवं भोपाल ग्रामीण क्षेत्र के कुल 4 लाख 7 हजार 216 उपभोक्ताओं को मई माह में 4 करोड़ 40 लाख रुपए की रियायत प्रदान की गई है। कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनकी विद्युत खपत के आधार पर टाइम ऑफ डे (ToD) योजना के अंतर्गत यह छूट प्रदान की गई है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री ऋषि गर्ग ने बताया है कि कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटरिंग पहल के अंतर्गत उपभोक्ताओं को सोलर ऑवर में बिजली उपयोग करने पर विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दिन के टैरिफ में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए यह सभी छूट अथवा प्रोत्साहन की गणना सरकारी सब्सिडी (यदि कोई हो) को छोड़कर की जा रही है।

कंपनी ने बताया है कि घरेलू, गैर घरेलू, सार्वजनिक जल कार्य, स्ट्रीट लाइट एवं निम्नदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की अवधि को सोलर ऑवर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उपभोग की गई ऊर्जा पर ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर में 20 प्रतिशत तक की छूट 10 किलोवाट तक स्वीकृत लोड/अनुबंध मांग वाले उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही है।

प्रबंध संचालक श्री ऋषि गर्ग ने आमजन एवं उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने परिसरों में स्मार्ट मीटर लगाने में सहयोग करें तथा स्मार्ट मीटर के उपयोग से होने वाले लाभों का अधिक से अधिक फायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर से सटीक रीडिंग, पारदर्शी बिलिंग एवं ऊर्जा खपत की रियल-टाइम मॉनिटरिंग संभव हो रही है। उल्लेखनीय है कि स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को बिजली की खपत को ट्रैक करने, ऊर्जा बचत करने तथा मोबाइल एप के माध्यम से कहीं से भी अपनी खपत की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। यह प्रणाली ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक सिद्ध हो रही है।

**स्मार्ट मीटर के फायदे**

- ऊर्जा की खपत को ट्रैक कर नियंत्रित करने और ऊर्जा की बचत करने में मदद करता है।
- बिजली की खपत को सटीक रूप से मापता है, जिससे बिल में कोई गलती नहीं होती।
- एप के जरिए मोबाइल पर रियल-टाइम डेटा देखकर ऊर्जा की खपत को नियंत्रित कर सकते हैं।
- ऊर्जा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिलती है, ताकि ऊर्जा की खपत को बेहतर बना सकते हैं।
- ऊर्जा की खपत को ऑनलाइन ट्रैक करने और नियंत्रित करने की सुविधा मिलती है।
- ऊर्जा की खपत को कम करने से पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव कम होता है।

## संक्षिप्त समाचार

### कलेक्टर ने वीसी के माध्यम से की समान नागरिक संहिता तथा जनकल्याण शिविरों सहित अन्य कार्यों की समीक्षा

**रायसेन (निप्र)।** कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में रविवार को आयोजित बैठक सह वीडियो कॉफ्रेंस में कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा ने अधिकारियों से प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के संबंध में नागरिकों से सुझाव संबंधी विकासखण्डवार सभी एसडीएम, जनपद सीईओ तथा सीएमओ से चर्चा की। साथ ही समान नागरिक सुझाव दर्ज कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने और सुझावों को दर्ज करानें के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में जिले में आयोजित किए जा रहे जनकल्याण शिविरों की समीक्षा करते हुए सभी एसडीएम, जनपद सीईओ तथा सीएमओ से कहा कि शिविरों का आयोजन नागरिकों तक शासन की योजनाओं का लाभ सुगमता से पहुंचाने और उनकी समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से किया जा रहा है। सभी अधिकारी शिविर में प्राप्त होने वाले आवेदनों का प्राथमिकता से निराकरण कराएं। साथ ही आगामी शिविरों मे अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित करने की कार्यवाही भी की जाए। बैठक में ज्ञान भारतम मिशन तथा 21 जून को विश्व योग दिवस कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियों के संबंध में चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों का दिशा-निर्देश भी दिए। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। विकासखण्डों से एसडीएम, जनपद सीईओ तथा सीएमओ वीसी के माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे।

### अवैध रेत खनन एवं परिवहन पर की गई कार्रवाई

#### अवैध रेत उत्खनन करने पर 02 जेसीबी जब्त

**सीहोर (निप्र)।** कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निर्देशानुसार खनिज, राजस्व एवं पुलिस के दल द्वारा जिले में अवैध खनन एवं परिवहन के विरूद्ध निरंतर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में बुधनी, रेहटी एवं इछावर तहसील के अंतर्गत चेकिंग के दौरान दल द्वारा रेहटी में रेत का अवैध उत्खनन करते हुए 02 जेसीबी जब्त की गई और रेहटी थाने की अभिरक्षा में दी गई।

### 4147 प्रतिभागियों ने ऑनलाइन पंजीयन कर किया योगाभ्यास

**बैतूल (निप्र)।** अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को जिला प्रशासन एवं नगर पालिका के सहयोग से आयुष विभाग और शिक्षा विभाग द्वारा शिवाजी ओपन ऑडिटोरियम बैतूल में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया।प्रातः 6:15 बजे आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर डॉ सौरभ संजय सोनवणे ने योगाभ्यास स्थल पहुंचकर व्यवस्थाओं एवं कार्यक्रम की जानकारी ली। जिला आयुष अधिकारी डॉ. योगेश चौकीकर ने बताया कि कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों, विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं नागरिकों ने सहभागिता कर ऑनलाइन जुड़कर योगाभ्यास का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के प्रयास में भाग लिया। जिले से कुल 4147 प्रतिभागियों ने ऑनलाइन पंजीयन कर योगाभ्यास किया, जबकि जिले के 17 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों सहित विभिन्न स्थानों पर 902 लोगों ने सामूहिक रूप से ऑनलाइन एवं ऑफलाइन योगाभ्यास में सहभागिता की। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग की ओर से श्री नर्मदा प्रसाद मिश्रा, योग प्रशिक्षक कुमारी पारुल पालीवाल, श्री सागर शिवनकर एवं श्रीमती गीता पवार सहित अन्य उपस्थित है।

■ किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध : कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना

# कृषि विज्ञान केन्द्र का भूमिपूजन, किसानों को मिलेगा आधुनिक कृषि तकनीकों का लाभ

**विदिशा (निप्र)।** विदिशा जिले के ग्राम बेरखेड़ी जैतू में आज कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत कृषि विज्ञान केन्द्र का भूमिपूजन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विधिवत पूजन-अर्चन कर कृषि विज्ञान केन्द्र के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री ऐदल सिंह कंषाना व विदिशा संसदीय क्षेत्र के विधायकगणों के साथ साथ अन्य जनप्रतिनिधि, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक समेत केन्द्र व प्रदेश के कृषि विभाग से संबंधित अधिकारियो के अलावा तथा बड़ी संख्या में कृषकगणो के अलावा अन्य मौजूद रहे।

### कार्यक्रम को संबोधित करते हुए

प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री ऐदल सिंह कंषाना ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से हरसंभव प्रयास कर रही हैं। इस दिशा में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं। कृषि मंत्री श्री कंषाना ने कहा कि केवल पारंपरिक खेती पर निर्भर रहने के बजाय किसानों को आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित करने की आवश्यकता है। कृषि के साथ-साथ पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन एवं अन्य कृषि आधारित गतिविधियों को अपनाकर किसान अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पशुपालन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और सरकार इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाओं का संचालन कर रही है।

उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे अपनी रुचि एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वैकल्पिक आजीविका गतिविधियों का चयन करें। शासन द्वारा इन क्षेत्रों में तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे किसानों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाया जा सके। श्री कंषाना ने कृषि उत्पादन बढ़ाने और भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए मिट्टी परीक्षण को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों की सुविधा के लिए 259 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं संचालित की जा रही हैं, जहां किसान अपनी भूमि की मिट्टी का परीक्षण करवा सकते हैं। परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए उर्वरकों एवं पोषक तत्वों का निर्धारित मात्रा में उपयोग करने से खेती की लागत कम होती है तथा उत्पादन में वृद्धि होती है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक खेती और आधुनिक तकनीकों को अपनाकर किसान अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। राज्य सरकार किसानों को जागरूक करने, नई तकनीकों से जोड़ने और कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। कृषि, पशुपालन, बागवानी और मत्स्य पालन जैसे विविध क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाकर किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं और प्रदेश को कृषि विकास के नए आयामों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि विज्ञान केन्द्र किसानों और वैज्ञानिकों के बीच सेतु का कार्य करते हैं। यहां किसानों को आधुनिक खेती, उन्नत बीज, नवीन कृषि तकनीकों, फसल संरक्षण, जैविक खेती तथा कृषि आधारित उद्यमों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य खेती को लाभकारी बनाना और किसानों की आय में निरंतर वृद्धि करना है। श्री चौहान ने कहा कि कृषि विज्ञान केन्द्र के स्थापित होने से विदिशा जिले के किसानों को वैज्ञानिक मार्गदर्शन स्थानीय स्तर पर प्राप्त होगा। इससे नई तकनीकों का तेजी से प्रसार होगा और किसान आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाकर उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ा सकेंगे। उन्होंने किसानों से खेती में नवाचारों को अपनाने और वैज्ञानिक सलाह के अनुरूप कार्य करने का आह्वान किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा के बेरखेड़ी जैतूमें किसानों की अनूठी 'पाठशाला' लगाकर खेती बदलने का बड़ा संकल्प सामने रखा।

### विदिशा में किसानों की पाठशाला

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरुआत में ही साफ कर दिया कि यह कार्यक्रम भीड़ जुटाने या भाषण देने के लिए नहीं, बल्कि किसानों की ट्रेनिंग के लिए है। उन्होंने मीडिया को भी बताया कि यहाँ आए किसान किसी बस या गाड़ी से भरकर नहीं लाए गए, जो सीखना चाहता है वह अपने साधन से आया है, इसलिए मंचीय औपचारिकताओं की जगह सीधी क्लास होगी। मंत्री श्री चौहान ने कहा कि यहाँ बैठे हर किसान को विद्यार्थी माना जाए, जिनके लिए वैज्ञानिक अपनी बात सीमित शब्दों में रखेंगे और फिर सीधे खेत में ले जाकर मशीनों और नई तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा।

### मॉडल KVK: 49 एकड़ की जीवंत प्रयोगशाला

बेरखेड़ी जट्टू में बनने वाला यह कृषि विज्ञान केंद्र 49 एकड़ जमीन पर देश का मॉडल KVK होगा, जहाँ इसी खरीफ सीजन से प्रदर्शन प्लॉटों पर आधुनिक तरीके से खेती शुरू होगी। शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि बिल्डिंग का इंतजार किए बिना खेत पर काम तुरंत शुरू होगा– किसान को आँखों से दिखाकर सिखाया जाएगा, सिर्फ सुनाकर नहीं। इस KVK से ICAR के 113 संस्थानों और 1700 से अधिक KVK–संस्थानों के नेटवर्क की रिसर्च सीधे विदिशा–अंचल के किसानों तक मोबाइल, डेमो और प्रशिक्षण के जरिए पहुंचाई जाएगी।

### वैज्ञानिक खेती का रोडमैप : ढाई एकड़ में सम्मानजनक आमदनी

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि जमीनें बँट–बँटकर छोटी हो गई हैं, लेकिन ढाई एकड़ (एक हेक्टेयर) में भी अगर इंटीग्रेटेड फार्मिंग ठीक से की जाए तो पूरे परिवार की आजीविका आराम से चल सकती है। इसके लिए विदिशा, रायसेन, सीहोर और देवास जिलों की मिट्टी, पानी और संसाधनों का वैज्ञानिक विश्लेषण करके फसल–पद्धति का रोडमैप तैयार किया गया है, जिसकी ट्रेनिंग इसी चक्र्च से दी जाएगी। खेत में मॉडल फार्म बना कर दिखाया जाएगा कि एक ही टुकड़े में अनाज, दलहन, तिलहन, बागवानी, पशुपालन, मछली–पालन, मधुमक्खी–पालन और मशरूम तक जोड़कर कैसे अधिकतम लाभ कमाया जा सकता है।

## गौभोजनम् अभियान के माध्यम से गौसेवा का दिया गया संदेश

**सीहोर (निप्र)।** सीहोर की सामाजिक संस्था 'संडे के सुकून' द्वारा संचालित गौसेवा अभियान 'गौभोजनम' का सफलतापूर्वक समापन किया गया। अभियान के माध्यम से ग्रीष्मकाल के दौरान नगर में विचरण करने वाले गौवंश को भोजन, पानी, पशु आहार एवं हरी घास उपलब्ध कराई गई। संस्था के सदस्यों ने बताया कि भीषण गर्मी के दौरान अनेक स्थानों पर गौवंश भोजन एवं पेयजल के अभाव में परेशान होते हैं तथा कचरे में भोजन तलाशने को विवश हो जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए गौभोजनम् अभियान प्रारंभ किया गया।

अभियान के अंतर्गत प्रतिदिन नगर के विभिन्न स्थानों पर सैकड़ों गौवंश के लिए भोजन एवं पेयजल की व्यवस्था की गई। अभियान के दौरान नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। अनेक लोगों ने अपने जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ तथा परिजनों की पुण्यतिथि के अवसर पर गौसेवा कर सामाजिक सरोकार का परिचय दिया। बच्चों एवं युवाओं ने भी बढ़-चढ़कर भाग लेते हुए गौवंश के लिए भोजन एवं जल की व्यवस्था में सहयोग किया। संस्था के सदस्यों द्वारा लगातार दूसरे वर्ष प्रतिदिन प्रातः गौसेवा वाहन के माध्यम से नगर में स्थापित भोजन पात्रों एवं जल पात्रों को भरा गया, जिससे सड़क पर विचरण करने वाले गौवंश को दिनभर भोजन एवं पेयजल उपलब्ध हो सका। इसके साथ ही संस्था द्वारा विभिन्न स्थानों पर लगाए गए पौधों एवं गमलों की भी नियमित सिंचाई की गई, जिससे पौधे हरे-भरे बने रहे। समापन अवसर पर संस्था के सदस्यों ने नागरिकों से प्रतिदिन प्रथम दो रोटियां गौवंश के लिए निकालने तथा गौसेवा की परंपरा को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि समाज की सहभागिता से गौसंरक्षण एवं गौसेवा के प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

## हरदा नगर पालिका में जनकल्याण शिविर संपन्न

### 268 आवेदनों का मौके पर किया निराकरण

**हरदा (निप्र)।** केन्द्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुँचाने तथा आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से जिले में 12 से 18 जून 2026 तक विशेष जनकल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत किया जा रहा है। शिविरों का मुख्य उद्देश्य शासन की योजनाओं से वंचित पात्र हितग्राहियों को चिन्हित कर लाभान्वित करना तथा लंबित शिकायतों का मौके पर ही समाधान करना है। इसी क्रम में रविवार को हरदा के नगर पालिका कार्यालय परिसर में आयोजित तीन दिवसीय जनकल्याण शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर के दौरान नागरिकों से विभिन्न योजनाओं के आवेदन प्राप्त कर उनका मौके पर ही निराकरण किया गया। शिविर में राजस्व, नगरीय निकाय, सामाजिक न्याय, जल प्रदाय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे और नागरिकों को एक ही छत के नीचे योजनाओं का लाभ दिया गया। शिविर में पीएम स्वनिधि योजना के 63 आवेदन, स्वनिधि से समृद्धि योजना अंतर्गत 5 प्रोफ़ाइलिंग, नवीन नल कनेक्शन के 11, विधवा पेंशन के 2, वृद्धावस्था पेंशन के 7, आय प्रमाण पत्र के 100, मूल निवासी के 80 आवेदनों का त्वरित निराकरण कर हितलाभ वितरण किया गया।नगर परिषद कार्यालय खिरकिया में 15 से 17 जून तक आयोजित होंगे शिविर जिले में 15 से 17 जून तक नगर परिषद खिरकिया में तीन दिवसीय जनकल्याणकारी शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में 15 जून को स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, डीईजीएम, कृषि विभाग, नागरिक आपूर्ति विभाग, लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

इसी प्रकार 16 जून को एनआईसी, स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा विभाग, कृषि विभाग व सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी शिविर में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा 17 जून को आयोजित शिविर में ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, महिला बाल विकास विभाग, जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र, पशुपालन विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग व श्रम विभाग के अधिकारी उपस्थित रहेंगे।नगर परिषद कार्यालय टिमरनी में 16 से 18 जून तक आयोजित होंगे शिविर जारी कलेण्डर अनुसार 16 से 18 जून तक नगर परिषद टिमरनी में तीन दिवसीय जनकल्याणकारी शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में 16 जून को स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, डीईजीएम, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, नागरिक आपूर्ति विभाग, लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

इसी प्रकार 17 जून को जनजातीय कार्य विभाग, कॉपरेटिव बैंक, ग्रामीया यांत्रिकी सेवा, जल संसाधन विभाग, पशुपालन विभाग व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शिविर में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा 18 जून को आयोजित शिविर में स्वास्थ्य विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी, डीईजीएम, कृषि विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम, लोक सेवा प्रबन्धन, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, जनजातीय कार्य विभाग व महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

## विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर पचमढ़ी में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन

**नर्मदापुरम (निप्र)।** विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय नर्मदापुरम द्वारा कार्यालय मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद पचमढ़ी में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। शिविर में रक्तदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए मानव सेवा एवं जीवन रक्षा के इस पुनीत कार्य में अपना योगदान दिया। शिविर के दौरान कुल 42 स्वैच्छिक रक्तदाताओं द्वारा रक्तदान किया गया। सिविल सर्जन डॉ. सुनीता कामले, आर एम ओ डॉ. गजेंद्र यादव एवं पैथोलॉजिस्ट डॉ. इज़हार खान के मार्गदर्शन मे जिला चिकित्सालय नर्मदापुरम की रक्तकोष टीम द्वारा रक्तदान की समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं। शिविर में जिला चिकित्सालय की ओर से डॉ. अदिति अग्रवाल, लेब टेक्नीशियन श्री पंकज शर्मा, श्री शुभम कटारे, सुश्री रक्षी खान, श्री रवि यादव एवं श्री धीरज मंडलोई उपस्थित रहे। साथ ही जिला रेडक्रॉस शाखा नर्मदापुरम से श्री शेर सिंह बड़कुड़ ने भी सहयोग प्रदान किया।

इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि स्वैच्छिक रक्तदान किसी भी जरूरतमंद मरीज के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को नियमित रूप से रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए।

## हरदा के ग्राम उड़ा में 'बावड़ी महोत्सव' का भव्य आयोजन, प्राचीन धरोहरों के संरक्षण का दिया संदेश

**हरदा (निप्र)।** मध्य प्रदेश शासन की मंशानुरूप एवं जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत हरदा विकासखंड के ग्राम उड़ा में स्थित ऐतिहासिक एवं प्राचीन बावड़ी पर भव्य 'बावड़ी महोत्सव' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा किया गया। आयोजन का उद्देश्य प्राचीन धरोहरों के संरक्षण, पुनर्जीवन तथा जल संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना था।

कार्यक्रम के दौरान वर्षों पुरानी इस ऐतिहासिक बावड़ी को आकर्षक रंगोलियों एवं सैकड़ों दीपों से सजाया गया। दीपों की मनमोहक रोशनी से जगमगाती बावड़ी ने उपस्थित लोगों को प्राचीन गौरव और सांस्कृतिक विरासत का एहसास कराया। ग्राम उड़ा स्थित कालू बाबा समाधि स्थल पर निर्मित यह बावड़ी गांव की महत्वपूर्ण पहचान होने के साथ-साथ प्राचीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण भी है।जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक श्री संदीप गोहर ने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत 5 जून से 30 जून तक विशेष गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

अभियान के अंतर्गत नवांकुर संस्थाओं, प्रस्फुटन समितियों एवं सीएमसीएलडीपी के विद्यार्थियों द्वारा संगोष्ठी, चौपाल बैठक, नुक्कड़ नाटक, जागरूकता रैली तथा दीवार लेखन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही श्रमदान के माध्यम से बावड़ियों की साफ-सफाई एवं जीर्णोद्धार का कार्य भी किया जा रहा है।

### विधायक मुकेश टंडन ने दिखाई हरी झंडी, हाई रिस्क गांवों में पहुंचकर मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव का देगा संदेश

# मलेरिया निरोधक माह के तहत जागरूकता रथ रवाना

**विदिशा (निप्र)।** मलेरिया निरोधक माह के अंतर्गत जिले में मच्छरजनित रोगों के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से रविवार को विदिशा विकासखंड के ग्राम बेरखेड़ी जेतू से मलेरिया जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक श्री मुकेश टंडन ने रथ को रवाना करते हुए आमजन से मलेरिया एवं अन्य मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए जागरूक रहने का आह्वान किया।

इस अवसर पर खादी ग्रामोद्योग के उपाध्यक्ष श्री राकेश सिंह जादौन, पूर्व जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामहित कुमार, जिला मलेरिया अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बताया गया कि मलेरिया जागरूकता रथ जिले के सभी विकासखंडों के हाई रिस्क ग्रामों में भ्रमण करेगा। रथ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी मच्छरजनित बीमारियों के कारण, लक्षण, बचाव एवं उपचार संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी।

साथ ही लोगों को अपने घरों और आसपास स्वच्छता बनाए रखने, जलभराव को रोकने तथा मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जागरूकता रथ केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया जांच की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

भ्रमण के दौरान बुखार से पीड़ित व्यक्तियों की मौके पर जांच की जाएगी तथा मलेरिया पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों को तत्काल निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। इससे बचाव के लिए मच्छरदानी का नियमित उपयोग, घरों के आसपास स्वच्छता बनाए रखना तथा पानी को जमा नहीं होने देना अत्यंत आवश्यक है।

### स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से की अपील

स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि बुखार आने पर तुरंत जांच कराएं और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामहित कुमार ने बताया कि जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों एवं आशा कार्यकर्ताओं के पास मलेरिया जांच की नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध है। नागरिक इन सेवाओं का लाभ उठाकर समय पर जांच और उपचार प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनसहभागिता और जागरूकता के माध्यम से ही मलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मलेरिया निरोधक माह के तहत संचालित यह जागरूकता अभियान जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने और मच्छरजनित रोगों की रोकथाम की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा।

राइट क्लिक

# टीएमसी : बागी गुट का यह 'दल शोधन' कहीं उल्टा न पड़ जाए !

अजय बोकिल

इसे दुरभिसंधि कहें या फिर राजनीतिक नवाचार, लेकिन भारतीय राजनीति में 'दल शोधन' का यह नया प्रयोग अपनी मूल पार्टी भारतीय राष्ट्रीय तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए बागियों के गुट और परदे के पीछ इसकी सूत्रधार भाजपा को भारी न पड़ जाए। क्योंकि टीएमसी के बागी 20 सांसदों के एक अनजान से राजनीतिक दल 'नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी आफ इंडिया' (एनसीपीआई) में 'विलय' और कथित विलय के बाद इस गुट को संसद में अलग बैठने की इजाजत स्पीकर ओम बिरला ने अभी नहीं दी है। कहने को यह रास्ता बागी सांसदों के भाजपा में विलय की कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए निकाला गया है, लेकिन खुद इस रास्ते में कई कांटे हैं। हालांकि जो कुछ हो रहा है, उससे देश में उन तमाम रजिस्टर्ड मगर चुनाव आयोग से गैर मान्यता प्राप्त सियासी पार्टियों की उम्मीदें बढ़ गई थीं, जो राजनीतिक कूड़ेदान में पड़ी थीं। क्योंकि उनके दिन भी फिर सकते हैं। अगर इस बागी गुट के विलय को संसद में अलग बैठने की मान्यता मिल गई तो जो पार्टी कल तक मच्छर की हैसियत भी नहीं रखती थी, वो आज 20 सांसदों के साथ मगरमच्छ की तरह अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को डराने की स्थिति में होगी। हम अभी तक अर्थशास्त्र में शेल कंपनियों (मुखौटा अथवा खोखा कंपनियां की बात सुनते थे, जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड तो होती हैं, लेकिन उन्हें केवल धन शोधन (मनीलांड्रिंग), काले धन को सफेद करने, पैसों की हेराफेरी तथा कर अपवंचन की नीयत से बनाया जाता है। लेकिन अब भाजपा के पश्चिम बंगाल मॉडल के तहत राजनीतिक 'दल शोधन' (पॉलिटिकल पार्टी लांड्रिंग) का नया जुमला वजूद में आ गया है। हालांकि इस 'दल शोधन फार्मूले' की कामयाबी में कई कानूनी और संवैधानिक पेंच हैं, लेकिन यह सफल हो गया तो हमे भविष्य में इसके नए एप्लीकेशन भी देखने को मिल सकते हैं।

नैतिक दृष्टि से इस 'दल शोधन' फार्मूले की आलोचना हो रही है। क्योंकि यह निष्ठाहीन, सिद्धांतविहीन सत्ता केन्द्रित राजनीति को वैधता प्रदान करने जैसा है। खुद भाजपा में भी इसके औचित्य पर लोग प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक जब आर्थिकी में इस तरह का धन शोधन अनुचित है तो राजनीति में इस दल शोधन को कैसे उचित माना जा सकता है? इस 'दल शोधन' ने देश में दलबदल कानून की प्रभावशीलता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अगर यानी कानूनी की पतली गलियां ही ज्यादा असरदार हैं तो ऐसे कानून का क्या मलतब? हालांकि भाजपा जैसी साधन से ज्यादा साध्य को परम मानने वाली पार्टी की सोच है कि तात्कालिक राजनीतिक लाभ किसमें यह देखना अहम है, न कि इसके दीर्घकालीन औचित्य-अनौचित्य के बारे में सोचना। पार्टी का मानना है कि संसद में मोदी सरकार द्वारा दो माह पूर्व लाए गए महिला आरक्षण और परिसीमन बिल दो तिहाई बहुमत के अभाव में गिर गए थे, उन्हें पास कराने के लिए किसी भी तरीके से संख्या बल जुटाना है। और इस 'पुनीत' कार्य को पूरा करने के लिए साम-दाम-दंड-भेद सब जायज है। हालांकि 'दल शोधन' इन पारंपरिक चार कारकों से भी अलग है।

इस स्तम्भ में पहले भी लिखा जा चुका है कि बीजेपी का राजनीतिक पश्चिम बंगाल मॉडल उसके पूर्ववर्ती मॉडलों की तुलना में अलग होगा, फिर भी इतना ज्यादा अलग होगा, यह राजनीतिक प्रेक्षकों के सोच के परे की बात रही है। माना यही जा रहा था कि भाजपा महाराष्ट्र मॉडल की तरह बंगाल में अब विपक्ष में बैठी टीमएमसी को तोड़कर नया गुट बनवाएगी या फिर उसे अपने में मर्ज कर लेगी। लेकिन ऐसा करने में कई कानूनी जटिलताएं और किंतु परंतु हैं और वक्त कम है, क्योंकि भाजपा को अर्जुन की तरह 2029 का लोकसभा चुनाव दिखाई दे रहा है। लिहाजा पुराने नुस्खों की जगह दूर की कौड़ी लाई गई। त्रिपुरा में रजिस्टर्ड एक गुमनाम सी पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया' पर दांव खेला गया। यह पार्टी त्रिपुरा के कुंडू दंपति और शांतनु डे ने 20 जनवरी 2023 को मजे-मजे में रजिस्टर्ड कराई थी। इसका मुख्यालय हावड़ा में है। लेकिन उसे चुनाव आयोग से मान्यता नहीं मिली है। एनसीपीआई ने उसी साल त्रिपुरा विस चुनाव में दो सीटों पर चुनाव लड़ा। सात किरणों वाली पेन की निब इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। चुनाव में उसे कुल जमा 822 वोट और 1.13 लाख रू. का चुनावी चंदा मिला। पति उत्तीय कुंडू और पत्नी शिवली कुंडू खुद को समाज सेवी बताते हैं। शिवली पहले कोषाध्यक्ष थीं, अब वो उससे अलग हो गई हैं। अब सवाल यह कि टीएमसी से अलग हुए 20 सांसदों के गुट को संसद में अलग मान्यता दिलाने की जगह एक अज्ञातकुलशील पार्टी में विलय का विचार कैसे और कहां से आया? ये सौदेबाजी किसने की? उत्तीय कुंडू का भाजपा से क्या सम्बन्ध है? यह चमत्कारिक विलय इतने गोपनीय ढंग से कैसे हो गया? और क्या ऐसा विलय जायज है? इस पार्टी का अध्यक्ष पद भी बागी सांसद ज्योतिप्रकाश चटर्जी के पास कैसे चला गया और पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष उत्तीय कुंडू ने खुशी खुशी अपनी पार्टी को हाई जैक कैसे हो जाने दिया? इसके पीछे कौन सा लेन-देन अथवा अंडरस्टैंडिंग बनी? सवाल कई हैं।

फिलहाल तो भाजपाई अपने इस नवाचारी दांव पर मुग्ध हैं। लेकिन जानकार इसकी वैधानिकता और स्थायित्व पर सवाल उठा रहे हैं। पहला और अहम सवाल तो यही है कि यही है कि क्या टीएमसी के चुनाव चिह्न और टिकट पर लोकसभा पहुंचे ये सांसद खुद को किसी और पार्टी के साथ जोड़ सकते हैं या नहीं? क्या संसद सदस्यों (या विधायकों) का कोई समूह खुद को अलग करके दूसरे राजनीतिक दल के साथ विलय कर सकता है या नहीं? या इसके लिए जिस राजनीतिक दल से वो निर्वाचित हुए हैं उसका सहमत होना आवश्यक है? संविधान विशेषज्ञ और लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य के मुताबिक इस मामले में क़ानून स्पष्ट है कि किसी राजनीतिक दल का तो विलय हो सकता है लेकिन निर्वाचित सदस्यों के समूह का नहीं, भले ही उनकी संख्या दो-तिहाई से अधिक हो। बागी सांसद चूंकि सांसद तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुने गए हैं, इसलिए उन पर दल-बदल विरोधी कानून लागू होगा। वे अपनी मर्जी से किसी भी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते, अगर वे ऐसा करते हैं, तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन यदि चुनाव आयोग इन बाग़ी सांसदों के दल को ही मूल तृणमूल कांग्रेस घोषित कर देता है तब यह क़ानून लागू नहीं होगा। आचार्य के मुताबिक मौजूदा क़ानून के तहत बाग़ी निर्वाचित सदस्यों की संख्या का कोई अर्थ नहीं है। कानून कहता है कि पहले मूल पार्टी का किसी दूसरी पार्टी में विलय होगा, फिर उसके सदस्य नए दल में शामिल सकते हैं। यानी बागी सांसद भले ही ख़ुद के एनसीपीआई में विलीन होने की घोषणा कर रहे हों लेकिन क़ानूनन वे टीएमसी के सदस्य ही हैं।

इसका सीधा अर्थ यह है कि 'दल शोधन' का यह रास्ता भारी जोखिमों से भरा है। राजनीतिक विश्लेषकों का तो कहना है कि यदि इस कथित विलय को मंज़ूरी मिल जाती है तो इसके गंभीर राजनीतिक मायने होंगे। यानी बड़ा झटका क्षेत्रीय पार्टियों को लगेगा। यह दल शोधन उनके राजनीतिक विनाश की घंटी है।

जहां तक उत्तीय कुंडू और भाजपा के रिश्तों की बात है तो बंगाल में भाजपा की बंपर जीत के बाद उत्तीय कुंडू ने 13 मई को अपने फेसबुक पेज पर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के साथ एक तस्वीर साझा की थी। इसका बंगाली में कैप्शन था 'सिर्फ सपने देखने के दिन खत्म हो गए हैं, अब उन्हें सच करने का समय है।' इसी तरह टीएमसी के बागी सांसदों के विलय से पहले उत्तीय ने फेसबुक पर एक पोस्ट साझा की। इसमें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की तस्वीरें थीं। पोस्ट में लिखा था, अहंकार पतन का कारण बनता है। सत्ता के नशे में लोग अक्सर भूल जाते हैं कि सत्ता स्थायी नहीं होती और जनता का समर्थन ही असली ताकत हैज्जो आज शिखर पर हैं, उन्हें कल समय को जवाब देना होगा।जाहिर है टीएमसी बागी गुट के विलय की पटकथा लिखने में उत्तीय और शुभेंदु की बड़ी भूमिका लगती है। दूसरी तरफ टीएमसी बागी गुटों में भी सांसद और विधायक अलग अलग राह चल रहे हैं। जबकि पार्टी पर ममता बैनर्जी की पकड़ अभी बहुत कमजोर नहीं हुई है। बहरहाल इस 'दल शोधन' का अंजाम क्या होगा, ये देखना दिलचस्प है। कहीं 'धन शोधन' की तरह यह भी भारी न पड़ जाए।

*लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।*
*संपर्क-*
*9893699939*
ajaybokil@gmail.com

## राजधानी में डीपीआई के बाहर चयनित शिक्षकों का प्रदर्शन

- बोले- शिक्षामंत्री जॉइनिंग की बात कहकर मुकरे, 9-10 बार भोपाल आ चुके, अभी तक नियुक्ति नहीं

**भोपाल (नप्र)।** मध्यप्रदेश में माध्यमिक शिक्षक (वर्ग-2) भर्ती 2024 के चयनित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर प्रदर्शन किया। सैकड़ों अभ्यर्थी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। सभी ने आयुक्त के नाम ज्ञापन भी सौंपा। उनका कहना है कि चॉइस फिलिंग पूरी हुए 6 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हुई। अभ्यर्थियों ने कहा कि हमें शिक्षा मंत्री ने कई बार आश्वासन दिया है। हम डीपीआई के बाहर 9-10 बार आ चुके हैं। केवल इसलिए कि नियुक्ति मिल जाए। शिक्षा मंत्री ने हमसे खुद कहा था जब नया सेशन शुरू होगा। आपकी जॉइनिंग करा देंगे। आज शिक्षा मंत्री कहकर मुकर गए।

### लोग बार-बार पूछ रहे जॉइनिंग कब होगी

शहडोल से आए सलमान ने कहा, रिजल्ट आने के बाद चॉइस फिलिंग भी हो गई, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुई। हमारे ऊपर सामाजिक दबाव बन रहा है। लोग बार-बार पूछते हैं कि जॉइनिंग कब होगी। कई लोग तो यह तक कहने लगे हैं कि हम उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। इससे हम सभी मानसिक रूप से परेशान हैं।

**हर सप्ताह केवल आश्वासन मिल रहा-** टीकमगढ़ से आए रमाकांत ने कहा- भर्ती प्रक्रिया शुरू हुए चार साल हो गए। 2022 से परीक्षा, रिजल्ट और चयन तक हर चरण में हमें आंदोलन करना पड़ा। हर सप्ताह सिर्फ आश्वासन मिलता है, लेकिन नियुक्ति नहीं हो रही। हममें से कई लोग यह तय करके आए हैं कि जब तक जॉइनिंग नहीं होगी, तब तक यहां से वापस नहीं जाएंगे।

बेहतर प्रबंधन और कुशलता से करायें नीट की परीक्षा, कहीं भी न रहे कोई कमी : मुख्यमंत्री

# नीट (अंडर ग्रेजुएट) परीक्षा 21 को

### प्रदेश के 30 जिलों के 283 परीक्षा केंद्रों में होगी परीक्षा

### मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वीसी से की नीट परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा

**भोपाल (नप्र)।** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नीट राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। इसके लिए सभी तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाएं। बेहतर प्रबंधन एवं कार्य कुशलता से पूरी पारदर्शिता के साथ यह परीक्षा सम्पन्न करायें। उन्होंने कहा कि परीक्षा आयोजन में किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी या त्रुटि न रहे। परीक्षा कराने में संलग्न सभी अधिकारी-कर्मचारी पूरी मुस्तैदी से अपने कर्तव्यों का पालन करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में नीट (अंडर ग्रेजुएट) परीक्षा-2026 की आगामी रविवार (21 जून) को होने वाली परीक्षा की तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा की।

यह परीक्षा प्रदेश के 30 जिलों के 283 परीक्षा केंद्रों में सम्पन्न कराई जाएगी। नीट परीक्षा की कुल अवधि सवा तीन घंटे की होगी। इस बार सभी परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नीट परीक्षा के समन्वयक उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि सभी परीक्षा केन्द्रों में लगाई जाने वाली बायोमैट्रिक मशीन, सीसीटीवी कैमरे एवं जैमर 19 जून को ही परीक्षा केन्द्रों में लगा दिए जाएं और 20 जून को इनका ट्रायल रन भी कर लिया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 21 जून को राष्ट्रपति महोदया का जबलपुर प्रवास प्रस्तावित है। जबलपुर शहर में 24 केंद्रों में नीट परीक्षा होनी है। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी यातायात का ऐसा प्रबंधन करें कि सभी परीक्षार्थी बिना

किसी बाधा के अपने-अपने परीक्षा केंद्रों में सुगमता से पहुंच जायें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि चूंकि नीट परीक्षा के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन में भी होने हैं, इन आयोजनों के कारण परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कोई कठिनाई न हो।

यातायात का बेहतर नियोजन करें। सुनिश्चित करें कि सभी परीक्षार्थी तय समय से पहले तक केन्द्रों में पहुंच जायें। किसी परीक्षार्थी को यदि सेंटर तक पहुंचने में आवागमन के साधन की परेशानी आ रही है तो प्रशासन और पुलिस अधिकारी किसी शासकीय वाहन या खुद अपने वाहन से उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में सहयोग करें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने परीक्षा केंद्रों वाले सभी 30 जिलों के कलेक्टर्स-एसपी एवं परीक्षा सम्पन्न कराने की व्यवस्थाओं से जुड़े अधिकारियों को वीसी से निर्देशित किया कि नीट परीक्षा की तैयारियों के लिए उपयोग में लाई गई एसओपी अब प्रदेश में होने वाली सभी परीक्षाओं में उपयोग में लाई जाएगी।

### इन जिलों में होगी नीट की परीक्षा

नीट (अंडर ग्रेजुएट) परीक्षा - 2026 मध्यप्रदेश के 30 जिलों के 283 परीक्षा केन्द्रों में होगी। यह परीक्षा इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, सागर, छिंदवाड़ा, बैतूल, भिंड, बालाघाट, अशोकनगर, छतरपुर, रतलाम, बड़वानी, खरगौन, धार, खंडवा, नर्मदापुरम्, दमोह, दतिया, देवास, गुना, मंदसौर, मुरैना, नीमच, राजगढ़, सिंगरौली, विदिशा और सतना जिले में होगी।

## पत्रकार को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर लूटा

### भोपाल में लिफ्ट मांगने के बहाने रोका, कमरे में ले जाकर धमकाया; ऑनलाइन ट्रांसफर कराए रुपए

**भोपाल (नप्र)।** भोपाल के निशातपुरा थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात घर लौट रहे एक पत्रकार को बदमाशों ने कथित रूप से चाकू की नोक पर बंधक बनाकर 32 हजार रुपए की लूट कर ली। आरोप है कि बदमाशों ने पत्रकार को एक कमरे में ले जाकर परिचितों से ऑनलाइन पैसे मंगवाए और अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

### लिफ्ट के बहाने बाइक सहित गिराया

जानकारी के अनुसार घटना सोमवार-मंगलवार दरमियानी रात करीब 12:30 बजे की है। पत्रकार अनुज मीणा अपना काम खत्म कर दोपहिया वाहन से घर लौट रहे थे। इसी दौरान निशातपुरा क्षेत्र में एक युवक ने उनसे लिफ्ट मांगी। अनुज के मुताबिक उन्होंने लिफ्ट देने से इनकार कर दिया। इसके बाद एक युवक अचानक उनकी बाइक के सामने आ गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर गिर गया।

**चाकू दिखाकर कमरे में ले गए-** पीड़ित का आरोप है कि बाइक गिरने के तुरंत बाद वहां पहले से मौजूद तीन अन्य युवक भी पहुंच गए। बदमाशों ने उनकी गर्दन पर चाकू अड़ा दिया और जबरन पास के एक कमरे में ले गए। कमरे में ले जाकर आरोपियों ने नकदी की मांग की। पर्याप्त राशि नहीं मिलने पर उन्होंने जान से मारने की धमकी देते हुए परिचितों से ऑनलाइन पैसे मंगवाने के लिए दबाव बनाया।

### सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

निशातपुरा थाना प्रभारी मनोज पटवा ने बताया कि घटना की सूचना मिली है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल प्रकरण दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। पुलिस क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके।

### खातों में ट्रांसफर कराए 32 हजार रुपए

अनुज मीणा के अनुसार आरोपियों ने अलग-अलग माध्यमों से कुल 32 हजार रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिए। घटना के बाद उन्हें करीब रात 3 बजे छोड़ा गया।

# मातम में बदलीं शादी की खुशियां

### गुना के दो सगे भाइयों की राजस्थान में डूबने से मौत, पार्वती नदी में गए थे नहाने

**गुना (नप्र)।** मध्य प्रदेश के गुना जिले के एक परिवार के लिए राजस्थान के बारां से बेहद हृदयविदारक खबर सामने आई है। बारां के छबड़ा क्षेत्र में स्थित पार्वती नदी में नहाने गए गुना निवासी दो सगे भाइयों और उनकी मां-बेटे समेत कुल चार लोगों की पानी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। सभी मृतक एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए छबड़ा के गूगौर गांव आए हुए थे। शादी वाले घर में इस सामूहिक मौत की खबर लगते ही शहनाइयों की गूंज चीख-पुकार और मातम में बदल गई।

### मछली का जाल बना काल

छबड़ा थाना प्रभारी राजेश खटाना से मिली जानकारी के मुताबिक, यह भीषण हादसा मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे हुआ है। शादी की रस्मों के बीच कुछ मेहमान गर्मी से राहत पाने के लिए पास ही बहने वाली पार्वती नदी में नहाने चले गए थे। नदी में नहाने के दौरान एक युवक का पैर पानी के भीतर बिछे मछली पकड़ने के जाल में बुरी तरह फंस गया। वह खुद को संभाल नहीं पाया और गहरे पानी में डूबने लगा।

**तीन लोग बचाने उतरे-** अपने साथी को डूबता देख वहां मौजूद तीन अन्य लोग बिना सोचे-समझे उसे बचाने के लिए नदी में आगे

बढ़े। लेकिन पानी की गहराई और नदी के बहाव के कारण वे तीनों भी खुद को नहीं बचा सके और देखते ही देखते चारों लोग नदी के गहरे पानी में समा गए।

**गुना के दो सगे भाइयों और मां-बेटे की हुई मौत-** नदी किनारे मौजूद अन्य लोगों के शोर मचाने पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोर निरंजन खारोल ने अपनी टीम के साथ तत्काल नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने चारों शवों को पानी से बाहर निकाला और तुरंत छबड़ा के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां ड्यूटी डॉक्टरों ने सभी को परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतकों में दो सगे भाई युनुस खान (18) पुत्र बंटी गौरी निवासी गुना मप्र, अरमान (17) पुत्र बंटी गौरी निवासी हड्डीमील गुना मप और मां-बेटे गुड्डी बाई (45) पत्नी रशीद खान निवासी छीपाबड़ौद एवं सलाम (22) पुत्र रशीद खान निवासी छीपाबड़ौद राजस्थान शामिल हैं।

**शादी वाले घर में पसरा सन्नाटा-** इस दर्दनाक हादसे में गुना के दो सगे भाइयों (अरमान और यूनुस) की एक साथ असमय मौत की खबर जैसे ही गुना में उनके निवास स्थान पर पहुंची, वहां कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। शादी के जश्न वाले घर में जहां कुछ घंटों पहले तक मंगल गीत गाए जा रहे थे, वहां अब सिर्फ अपनों को खोने का मातम पसरा हुआ है।

### मुख्यमंत्री ने डॉ. प्रफुल्ल चंद्र राय की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

**भोपाल (नप्र)।** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारतीय रसायन विज्ञान के जनक व महान शिक्षाविद् डॉ. प्रफुल्ल चंद्र राय की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है। डॉ. राय ने देश में 'बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स वर्क्स लिमिटेड' की स्थापना कर दवा उद्योग की नींव रखी थी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि डॉ. प्रफुल्ल चंद्र राय ने देश की इस पहली दवा कंपनी के जरिए उद्यमिता, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की अलख जगाई। वे हम सभी के लिए सदैव प्रेरणापुंज बने रहेंगे।

### मुख्यमंत्री ने श्रद्धेय चित्तरंजन दास की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

**भोपाल (नप्र)।** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महान स्वतंत्रता सेनानी और देशबंधु के नाम से सुप्रसिद्ध श्रद्धेय चित्तरंजन दास की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्व. श्री चित्तरंजन दास ने अपना जीवन देश की आजादी और गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। राष्ट्र निर्माण के लिए उनका त्याग और स्वराज को लेकर उनके विचार सदैव अनुकरणीय रहेंगे।

# 14 साल बाद सत्यनारायण शर्मा की विधानसभा में वापसी

## अपर सचिव पद पर किया ज्वाइन

**भोपाल ( न. प्र. )।** करीब 14 वर्ष तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय के पूर्व बर्खास्त अधिकारी सत्यनारायण शर्मा ने मंगलवार को अपर सचिव पद पर पुनः कार्यभार ग्रहण कर लिया। उनकी बहाली न्यायालय के आदेशों और अवमानना याचिका के बाद हुई है।

जानकारी के अनुसार श्री शर्मा को वर्ष 2012 में यह कहते हुए सेवा से पृथक कर दिया गया था कि उन्होंने नियमों के विपरीत नौकरी प्राप्त की थी तथा नियुक्ति के लिए आवश्यक निर्धारित योग्यताएं उनके पास नहीं थीं। उनकी नियुक्ति उस समय हुई थी जब श्रीनिवास तिवारी मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष थे।

बर्खास्तगी के आदेश को शर्मा ने न्यायालय में चुनौती दी थी। इसके बाद मामला लंबे समय तक विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं और न्यायिक सुनवाई में उलझा रहा। पिछली विधानसभा के कार्यकाल में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने उनकी बहाली का निर्णय लिया था, लेकिन सचिवालय स्तर पर उस पर अमल नहीं हो सका और मामला फाइलों में ही अटका रहा।

इसके बाद शर्मा ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के बहाली संबंधी निर्णय को लागू करने के निर्देश दिए।

आरोप है कि इसके बावजूद विधानसभा सचिवालय ने कार्रवाई नहीं की। इस पर शर्मा ने सचिवालय के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर की। अवमानना की कार्यवाही के बीच विधानसभा सचिवालय ने अंततः उनकी बहाली के आदेश जारी किए, जिसके बाद मंगलवार को उन्होंने अपर सचिव पद पर अपनी ज्वाइनिंग दे दी। यह मामला विधानसभा सचिवालय की नियुक्ति और सेवा संबंधी प्रक्रियाओं पर प्रश्न उठाता है।